सुबह सवेरे

A Daily News Magazine

इंदौर

सोमवार, 21 जुलाई, 2025

इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 10 अंक 282, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

प्रसंगवश

निजी क्षेत्र में आरक्षण की ओर बढ़ रही है राहुल की राजनीति?

पंकज श्रीवास्तव

राहुल गांधी ने हाल की बैठकों और बयानों में निजी क्षेत्र में आरक्षण की ज़ोरदार वकालत की है। क्या यह सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है या सियासी रणनीति? कांग्रेस आजकल अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के प्रतिनिधित्व को लेकर मुखर है। राहुल गाँधी लगातार जाति जनगणना की मांग उठा रहे हैं, जिसका मकसद ओबीसी समुदाय की वास्तविक सामाजिक-आर्थिक स्थिति का पता लगाना है। अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के बारे में सामान्य जनगणना से जानकारी मिल जाती है, लेकिन ओबीसी की स्थिति स्पष्ट करने के लिए व्यापक डेटा की जरूरत है।

इसी दिशा में, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ओबीसी सलाहकार परिषद का गठन किया। 15 जुलाई 2025 को बेंगलुरु में हुई इस परिषद की बैठक में तीन अहम प्रस्ताव पारित किए गए, जिन्हें 'बेंगलुरु घोषणापत्र' के रूप में जाना जा रहा है। ये प्रस्ताव हैं-

1. राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना: तेलंगाना मॉडल की तर्ज पर 2. आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा हटाने की माँग 3. निजी शैक्षिक संस्थानों में ओबीसी कोटा लागू करना।

लेकिन इस बैठक में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एक क़दम आगे बढ़ते हुए निजी क्षेत्र में आरक्षण की माँग उठायी। उन्होंने निजी क्षेत्र की नौकरियों, सरकारी प्रोन्नतियों, ठेकों और वित्तीय सहायता योजनाओं में ओबीसी के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण या जाति जनगणना के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व की माँग की। यह मांग बेंगलुरु घोषणापत्र से भी आगे की है और इसने सियासी हलचल मचा दी है।

1932 में महात्मा गांधी और डॉ.बी.आर. आंबेडकर के बीच हुए पूना पैक्ट ने वंचित समुदायों के लिए विधायिका में आरक्षित सीटों की नींव रखी। अंग्रेजों के प्रस्तावित कम्युनल अवार्ड में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की बात थी, जिसका गाँधी जी ने विरोध किया था, जबकि डॉ. आंबेडकर समर्थन में थे। अंततः पूना पैक्ट के तहत तय हुआ कि सभी नागरिक समान रूप से वोट देंगे, लेकिन विधायिका में सीटें और सरकारी नौकरियों में आरक्षण वंचित समुदायों के लिए सुनिश्चित होगा।

संविधान ने इस आधार पर अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया। लेकिन इस व्यवस्था को चुनौती देने वाली ताक़तें भी सक्रिय थीं। संवैधानिक समता के सिद्धांत के खिलाफ़ इसे अदालत में चुनौती दी गई।

जवाहरलाल नेहरू सरकार ने 1951 में पहला संविधान संशोधन कर यह सुनिश्चित किया कि समाज के कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान समानता के अधिकार के खिलाफ नहीं माने जायेंगे।

1979 में बिहार के मुख्यमंत्री रहे बी.पी. मंडल की अध्यक्षता में गठित आयोग ने 1980 में दी गयी अपनी रिपोर्ट में देश की 52 प्रतिशत आबादी को ओबीसी के रूप में चिह्नित किया और 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की। लेकिन इसे लागू करने में एक दशक लग गया। 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू कीं, जिसका तीखा विरोध हुआ। मंडल आयोग की सिफारिशों को मानते हुए सरकारी नौकरियों में आरक्षण तो लागू किया गया, लेकिन वित्तीय सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की बात पर चर्चा नहीं हुई। इसी तरह भूमि सुधार को लेकर की गई मंडल आयोग की सिफ़ारिशों को भी नज़रअंदाज़ कर दिया गया। जो भी हो, मंडल कमीशन के ज़रिए ओबीसी वर्ग एक नयी राजनीतिक ताक़त के रूप में गोलबंद हुआ जिससे घबराकर बीजेपी ने जवाब में कमंडल की राजनीति शुरू की और राम मंदिर आंदोलन को तेज कर दिया।

1991 में नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में शुरू हुए उदारीकरण ने निजी क्षेत्र को नई ताक़त दी। लेकिन इसका लाभ मुख्य रूप से उन लोगों को मिला, जिनके पास पहले से सामाजिक और आर्थिक पूंजी थी। सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी कम होने के साथ ही आरक्षित वर्ग की नौकरियाँ भी प्रभावित हुईं। ऐसे में निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात उठने लगी। अगली अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इस मुद्दे को ठंडा रखने की भरसक कोशिश की। वाजपेयी काल में सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने के लिए बाक़ायदा विनिवेश मंत्रालय बना दिया गया था। 2004 में यूपीए सरकार के साझा न्यूनतम कार्यक्रम में निजी क्षेत्र में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की बात शामिल की गयी। 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 'कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज' (सीआईआई) को संबोधित करते हुए चेतावनी दी कि अगर उद्योग जगत स्वेच्छा से वंचित तबकों के लिए सकारात्मक कदम नहीं उठाएगा, तो निजी क्षेत्र में आरक्षण का राजनीतिक दबाव बढ़ेगा।

लेकिन उद्योग जगत ने इसका तीखा विरोध किया। तर्क दिया गया कि- निजी क्षेत्र में आरक्षण मेरिट और दक्षता को प्रभावित करेगा, यह वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारतीय कंपनियों को कमजोर करेगा, सरकारी हस्तक्षेप निजी क्षेत्र को स्वीकार नहीं।

सीआईआई ने डॉ. जे.जे. ईरानी की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनाई, जिसने निजी क्षेत्र में आरक्षण से इंकार कर दिया। हालांकि, कुछ सांकेतिक उपायों का वादा किया गया, जैसे एससी/एसटी उद्यमियों को बढ़ावा देना, लेकिन ये वादे ज्यादातर कागजी साबित हुए।

आज राहुल गांधी सामाजिक न्याय को कांग्रेस की पहचान बनाने में जुटे हैं। उनकी जाति जनगणना की माँग को पहले मजाक बनाया गया। लेकिन अब मोदी सरकार को इस मांग को स्वीकार करना पड़ा है। लेकिन कोशिश इसकी धार कमज़ोर करने की है। ऐसे में सिद्धारमैया ने निजी क्षेत्र में आरक्षण की माँग करके बता दिया है कि राहुल किस राह पर हैं। जाति जनगणना के बाद आने वाले आँकड़ों को देखते हुए इस माँग का तेज़ होना स्वाभाविक है।

यह माँग बीजेपी और आरएसएस के लिए असहज है। कॉरपोरेट जगत भी इसका विरोध करेगा, क्योंकि ऐतिहासिक कारणों से भारत का उद्योग जगत सवर्ण-प्रधान रहा है और उसने सामाजिक न्याय को लेकर कभी दिलचस्पी नहीं दिखायी। कांग्रेस के ख़िलाफ़ कॉरपोरेट मीडिया का लगातार हमलावर रहने के पीछे यह भी एक कारण है। निजी क्षेत्र में आरक्षण केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं है। यह सामाजिक समावेशिता और आर्थिक समानता का सवाल है। अगर दलित, आदिवासी और ओबीसी समुदायों को निजी क्षेत्र में अवसर मिले, तो यह देश की सामाजिक-आर्थिक तस्वीर बदल सकता है। अमेरिका जैसे देशों में भी प्रतिनिधित्व के नियम हैं, ताकि हर नस्ल और समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित हो।

जैसा कि मनमोहन सिंह ने कहा था, 'ऐसे विचार को नहीं रोका जा सकता, जिसका समय आ गया है।' निजी क्षेत्र में आरक्षण का विचार अब अपरिहार्य लगता है। अगर यह माँग मान ली जाती है, तो यह भारत के सामाजिक ढांचे में एक नई क्रांति ला सकती है।

(सत्य हिंदी डॉट कॉम पर प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

'आफत' की बारिश
राजस्थान-यूपी के बुरे हाल

नई दिल्ली (एजेंसी)। राजस्थान में हो रही भारी बारिश आफत बन गई है। नागौर में तालाब भर गए हैं और पानी बाहर आ गया है, सड़क पर सैकड़ों मछलियां तैर रही है। वहीं, पिछले 24 घंटों में बारिश के कारण अलग-अलग हादसों में 7 लोगों की मौत हो गई। यूपी में लगातार बारिश से गंगा, यमुना और मंदाकिनी जैसी नदियां उफान पर हैं। काशी में 84 घाट डूबने के बाद अब गंगा का पानी अस्सी घाट की सड़क तक पहुंच गया है। गंगा के साथ वरुणा नदी में बाढ़ आ गई है। उधर बिहार के कई नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। पटना में गंगा नदी उफान पर है। पटना डीएम ने जिले के 78 स्कूलों को 21 जुलाई तक बंद रखने का आदेश दिया है। वहीं, जम्मू-कश्मीर में लैंडस्लाइड के चलते कश्मीर जाने वाला मार्ग बंद हो गया है। मौसम विभाग ने कर्नाटक, बिहार, सिक्किम, बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, उत्तर-दक्षिण कर्नाटक और उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र के कुछ हिस्सों में रविवार को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं, हिमाचल में कुल 141 सड़कें अभी भी बंद हैं। मुंगेर में देर रात से हो रही लगातार बारिश के बाद गंगटी नदी में उफान के बाद तारापुर खड़गपुर का संपर्क पूरी तरह से टूट गया। पानी के तेज बहाव के कारण यहां का डायवर्सन भी टूट गया है। जोधपुर के बालेसर में 175 (7 इंच) बरसात हुई। जोधपुर में शनिवार रात गुलजारपुरा इलाके में एक जर्जर मकान गिर गया। हालांकि हादसे में जनहानि नहीं हुई। जोधपुर के शेरगढ़ में भारी बारिश के कारण 40 साल पुराना बांध टूट गया। प्रशासन ने ढाणियों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया।

- नागौर जिले में सड़क पर तैरती नजर आई मछलियां
- काशी की कॉलोनियों में बाढ़,पटना में उफान पर गंगा

अब तक की सफलतम विदेश यात्रा रही दुबई और स्पेन की यात्रा : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री डॉ. यादव 7 दिन की विदेश यात्रा से स्वदेश लौटे

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 7 दिन की दुबई और स्पेन की विदेश यात्रा से रविवार को स्वदेश लौट आए। वैदेशिक संबंधों को नई ऊर्जा देने वाली दुबई और स्पेन की इस यात्रा को मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सफलतम यात्रा निरूपित किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की 7 दिवसीय दुबई और स्पेन की यात्रा के बाद वापसी पर स्टेट हेंगर पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यात्रा की सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दूर-दृष्टि और कुशल नेतृत्व को दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मीडिया से चर्चा में कहा कि प्रदेश में अलग-अलग सेक्टर में काफी निवेश की संभावनाएं हैं। दुबई और स्पेन के 7 दिन के प्रवास से मध्यप्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की अच्छी संभावनाएं बनी है। यात्रा के दौरान कई विदेशी कंपनियों से मध्यप्रदेश में निवेश और नॉलेज शेयरिंग के लिए करार भी हुए हैं।

लगभग 30.77 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि इससे पहले मध्यप्रदेश में रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव और भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से लगभग 30.77 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। निवेश धीरे-धीरे धरातल पर भी उतर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इस विदेश यात्रा से मध्यप्रदेश में कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, खनन, उद्योग और पर्यटन विकास के क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएं निकलकर सामने आई हैं, जिससे रोजगार के नए अवसरों के साथ-साथ औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश अब बड़ी तेजी से निवेश के लिए एक आदर्श राज्य के रूप में उभर रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज करेंगे नवीन विधायक विश्राम-गृह का भूमि-पूजन

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य एवं विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में सोमवार, 21 जुलाई को प्रातः 10:30 बजे विधायक विश्राम गृह खण्ड-क्र.-1 के सामने, विधायक विश्राम गृह परिसर भोपाल में नवीन विधायक विश्राम गृह निर्माण कार्य का भूमि-पूजन होगा। कार्यक्रम में संसदीय कार्य मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय और लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह भी शामिल होंगे।

लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह ने रविवार को भूमि-पूजन स्थल का निरीक्षण किया और भूमि-पूजन कार्यक्रम की उत्कृष्ट तैयारियों के अधिकारियों को निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि यह नवीन विधायक विश्राम गृह लगभग 160 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा और इसमें सभी आवश्यक व्यवस्थाओं के साथ 102 फ्लैट्स का निर्माण प्रस्तावित है।

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

सुप्रभात

पहले
आधे कदम तक
लड़खड़ाया

अगले
आधे कदम में
संभलकर चलना सीखा

दूसरा
आधा कदम
सधा हुआ था

अगले
आधे कदम में
यात्रा पूरी थी

तीसरा कदम
उठाने के पहले ही
ईश्वर ने उंगली थाम ली
कांधे पर बैठा लिया

योग्य की नहीं
योग्यता की परीक्षा होती है

फिर ईश्वर
सिर-आंखों पर बैठा लेता है

योग्य को
स्वयं दिखाता फिरता है।

- राग तेलंग

कोलकाता में मुख्य शूटर समेत 8 आरोपी गिरफ्तार
चंदन मिश्रा हत्याकांड: इनमें एक महिला भी,नीतिश ने डीजीपी को किया तलब

पटना (एजेंसी)। पटना के पारस अस्पताल में 17 जुलाई को हुई गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या के मामले में पटना पुलिस और पश्चिम बंगाल एसटीएफ की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। कोलकाता से शूटर तौसीफ उर्फ बादशाह, उसके मौसेरे भाई निशु खान समेत 8 को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों के अलावा सचिन सिंह, हर्ष उर्फ हरीश कुमार, भीम कुमार और एक महिला अल्पना दास को भी दबोचा गया है। एसटीएफ और पटना पुलिस टीम ने शनिवार की शाम को कोलकाता की अलग-अलग जगहों पर छापा मारा। कोलकाता से पकड़े गए आरोपियों पर चंदन मिश्रा की हत्या करने के बाद पटना से कोलकाता भगाने, हथियार देने और साजिश में शामिल होने का आरोप है। बादशाह के परिजन ने ही इन पांचों शूटरों के कोलकाता भागने का सुराग दिया था। जिन पांच शूटरों ने वारदात को अंजाम दिया, उनमें तौसीफ उर्फ बादशाह, मोनू, बलवंत, अभिषेक और नीलेश शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार कोलकाता में गिरफ्तार 8 आरोपियों को कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पुलिस पटना लेकर आएगी। इधर रविवार को मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने डीजीपी को तलब किया। सीएम ने केस की पूरी जानकारी ली। पटना एसपी के मुताबिक, तौसीफ के भाई निशु खान के आवास पर हत्या की साजिश रची गई थी। वारदात को मुख्य अपराधी तौसीफ उर्फ

बादशाह लीड कर रहा था। 6 अन्य को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। पटना पुलिस चंदन मिश्रा हत्याकांड का रविवार को खुलासा कर सकती है। वहीं, पटना में लापरवाही बरतने वाले 1 दरोगा, 2 एसआई और 2 सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। तौसीफ के परिजनों से सुराग मिलने के बाद एसटीएफ और पटना पुलिस की टीम फ्लाइट से कोलकाता गई। पटना में बैठे अधिकारी पांचों शूटरों के मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी देखने में जुट गए। सीसीटीवी से सुराग मिलने के बाद एसटीएफ व कोलकाता पुलिस ने न्यूटाउन के सुखी वृष्टि अपार्टमेंट के दो फ्लैटों में छापेमारी की। फ्लैट नंबर 206 और 406 से कुछ लोगों को उठाया गया, लेकिन पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। इनसे मिले सुराग के आधार पर आनंदपुर, लेदर कॉम्प्लेक्स और भांगर इलाके में एक कार को पकड़ा गया।

भोपाल का तापमान
अधिकतम 35 °c
न्यूनतम 30°c

सुबह सवेरे
इंदौर ■ सोमवार, 21 जुलाई 2025

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।
चाणक्य नीति

सीएम योगी ने किया ऐलान, कांवड़ियों पर बरसाए फूल

शिवभक्तों के वेष में छिपे उपद्रवियों की होगी पहचान

मेरठ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा अपने चरम पर है। श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों को संदेश देते हुए साफ चेतावनी दी–कांवड़ यात्रा की आड़ में उपद्रव बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व कांवड़ियों के वेश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें तुरंत पहचानकर प्रशासन को सूचना दी जानी चाहिए। दिल्ली से लौटते समय सीएम योगी ने गाजियाबाद के प्रसिद्ध दूधेश्वरनाथ मंदिर में जलाभिषेक किया और फिर बागपत में हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा की। इसके बाद उनका काफिला मेरठ पहुंचा, जहां मोदीपुरम स्थित दुल्हेड़ा

चौकी के पास विशेष मंच पर योगी ने 'ऑपरेशन सिंदूर' कांवड़ को हाथ से रोककर उस पर 4-5 बार पुष्पवर्षा की। कांवड़ियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा,शिवभक्ति का यह पर्व लोकमंगल का प्रतीक है। हर शिवभक्त को चाहिए कि वह दूसरों की असुविधा को समझे और यात्रा को अनुशासित रखे। उन्होंने प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाओं की व्यवस्थाओं की भी सराहना की और यातायात की सुचारू व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि यात्रा मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। किसी भी तरह की अव्यवस्था या उपद्रव करने वालों की पहचान कर उनके पोस्टर सार्वजनिक किए जाएंगे और उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया के माध्यम से भी कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें जनता और प्रशासन मिलकर बेनकाब करेंगे। सीएम योगी के कार्यक्रम से पहले सरधना के पूर्व विधायक और भाजपा के फायरब्रांड नेता संगीत सोम की निजी गाड़ी को पुलिस ने कार्यक्रम स्थल के पास रोक दिया।

उद्धव के बाद अब सीएम फडणवीस से मिले आदित्य ठाकरे

मुंबई (एजेंसी)। शिवसेना (यूबीटी) नेता और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने शनिवार शाम

- **गर्माई महाराष्ट्र की सियासत,सरकार में आने का ऑफर भी दे चुके**

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दोनों अलग-अलग कार्यक्रम के लिए 3 घंटे मुंबई के सोफिटेल होटल में थे। इस दौरान दोनों की

करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। हालांकि, दोनों नेताओं ने किसी भी मीटिंग से इनकार किया है। सीएम ऑफिस के अनुसार मुख्यमंत्री होटल में मौजूद थे, लेकिन आदित्य ठाकरे से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। सीएम किसी और कार्यक्रम के लिए होटल में

आए थे, जबकि आदित्य डिनर के लिए अपने दोस्तों के साथ होटल में मौजूद थे। इससे पहले 17 जुलाई को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले थे। यह मुलाकात विधान परिषद अध्यक्ष राम शिंदे के कमरे में हुई थी।

चुनाव से पहले बिहार के क्राइम ग्राफ ने बढ़ाई चिंता

- **महागठबंधन ने नीतिश सरकार को घेरने का बनाया प्लान , आज से सत्र**

पटना (एजेंसी)। बिहार विधानसभा चुनाव इसी साल की आखिरी तिमाही में होने हैं। चुनाव से पहले हाल ही में जिस तरह से

- **बिहार में बढ़ती हत्याओं से घिर गए हैं सीएम नीतिश कुमार**

हत्या और अलग-अलग तरीके के अपराध के मामले में बढ़े हैं, उसके चलते राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। वहीं कानून व्यवस्था को लेकर सभी के निशाने पर सीएम नीतिश कुमार हैं। सबसे ताजा घटना

गुरुवार को हुई जब पांच बंदूकधारियों ने पैरोल पर छूटे एक कुख्यात अपराधी की पटना के एक निजी अस्पताल में गोली मारकर हत्या कर दी। विपक्ष लंबे समय से नीतिश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर हमला बोल रहा है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि एक अचेत मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार अराजकता में डूब गया है। दिलचस्प बात यह भी है कि लोकजनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और एनडीए के साथी चिराग पासवान ने भी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हालिया हत्याएं बिहार में कानून-व्यवस्था के पूरी तरह से ध्वस्त होने को दर्शाती हैं। राज्य के सीएम नीतिश कुमार को बिहार में जंगल राज के खात्मे का क्रेडिट दिया जाता है।

संसद सत्र आज से, 'हंगामेदार' रहने के हैं आसार

नई दिल्ली (एजेंसी)। कल यानी 21 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। इससे पहले केंद्र सरकार ने सभी पार्टियों की बैठक बुलाई, जो लगभग डेढ़ घंटे

- **सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में उठे कई अहम मुद्दे**

तक चली। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने मीडिया से बातचीत में कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। हालांकि, यह सभी चर्चाएं संसद के नियमों के तहत होंगी। सर्वदलीय बैठक पर बात करते हुए किरण रिजिजू ने कहा, सरकार ने सभी दलों की बातें सुनी हैं। सदन में पहलगाम हमले और

- **'ऑपरेशन सिंदूर' पर चर्चा को तैयार है मोदी सरकार**

ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सदन में मौजूद रहेंगे। संसद का आगामी सत्र 21 जुलाई 2025 से 21 अगस्त 2025 तक चलेगा। वहीं, स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर 13 और 14 अगस्त को संसद की बैठक नहीं होगी। मानसून सत्र में विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर पार्टियां संसद में चर्चा करना चाहती हैं। सरकार खुले मन से चर्चा के लिए तैयार है। सरकार नियमों और परंपराओं के अनुसार काम करती है और उन्हें बहुत महत्व देती है। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। सरकार इस दौरान दोनों सदनों में 17 विधेयक पेश कर सकती है। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने कई अहम मुद्दों पर सरकार का ध्यान खींचा। सरकार ने सभी मुद्दों पर सकारात्मक रुख दिखाया और नियमों के अनुसार चर्चा करने की बात कही। किरेन रिजिजू ने बैठक के बाद कहा कि सरकार संसद में उचित जवाब देगी। उनसे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के युद्धविराम संबंधी दावे के बारे में सवाल पूछा गया था। रिजिजू ने यह भी कहा कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है।

हुर्रियत का मतलब नहीं, भारत में अपनी जगह बनाएं

पूर्व अलगाववादी नेता की कश्मीरी युवाओं को सलाह

श्रीनगर (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर में मुख्य धारा की राजनीति में शामिल हुए तमाम अलगाववादी नेता अब राज्य के युवाओं के भी हुर्रियत प्रेम से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। पूर्व अलगाववादी नेता बिलाल गनी लोन ने भी हुर्रियत को मौजूदा समय में पूरी तरह से अप्रासंगिक बताया। इतना ही नहीं उन्होंने जम्मू-कश्मीर में हिंसा और गड़बड़ी फैलाने के लिए पाकिस्तान को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वह कभी भी कश्मीर को अपने साथ नहीं जोड़ सकता। पीटीआई से बात करने हुए जम्मू-कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के संस्थापक अब्दुल गनी लोन के बेटे बिलाल ने कहा कश्मीर में हुर्रियत की प्रासंगिकता पर बात की। उन्होंने कहा,अगर आप आज की तारीख में देखेंगे तो हुर्रियत मौजूदा कश्मीर में कहीं भी मौजूद नहीं है। इसका कुछ काम नहीं है।

उमरिया में कुत्तों के हमले से चीतल की मौत

तीन घंटे तक नहीं पहुंची वन विभाग टीम, एसडीएम बोले–लापरवाह अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

उमरिया (नप्र)। उमरिया जिले के चंदिया वन क्षेत्र में रविवार को एक मादा चीतल पर कुत्तों ने हमले कर दिया। यह घटना पथरहठा गांव की ददरी कॉलोनी में हुई। चीतल के शरीर पर कुत्तों के दांत के निशान साफ दिख रहे थे।

तीन घंटे तक नहीं पहुंची वन विभाग की टीम– ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को खबर दी। हालांकि अधिकारियों ने कहा कि ये इलाका उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इसलिए वे मौके पर नहीं आए। दरअसल, ये इलाका बांधवगढ़ और सामान्य वन मंडल उमरिया की सीमा में आता है। वन विभाग की टीम करीब तीन घंटे तक मौके पर नहीं पहुंची। तब ग्रामीणों ने अनुविभागीय अधिकारी को सूचना दी। एसडीएम कुलदीप त्रिपाठी के आदेश पर चंदिया वन परिक्षेत्र की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। एसडीएम कुलदीप त्रिपाठी ने कहा कि कहा कि जिन कर्मचारियों ने लापरवाही दिखाई, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पंजाब में एएपी की महिला एमएलए का इस्तीफा नामंजूर

पार्टी प्रधान ने घर जाकर मनाया,मॉडलिंग-सिंगिंग के लिए पढ़ाई तक छोड़ दी थी

चंडीगढ़ (एजेंसी)। पंजाब में आम आदमी पार्टी (एएपी) ने खरड़ से महिला एमएलए अनमोल गगन मान का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। उनके इस्तीफे और राजनीति छोड़ने के ऐलान के 24 घंटे के भीतर पार्टी के प्रदेश प्रधान अमन अरोड़ा मान के घर पहुंचे। इसके बाद अरोड़ा ने कहा- मान से पारिवारिक माहौल में मुलाकात हुई। पार्टी ने विधायक पद से उनका इस्तीफा नामंजूर करने का फैसला किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर

लिया। उन्होंने उनसे पार्टी और क्षेत्र की प्रगति के लिए मिलकर काम करते रहने का आग्रह किया। बता दें कि अनमोल गगन मान पंजाब की मशहूर सिंगर व मॉडल रह चुकी हैं। इसके लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी थी। इसके बाद वह मिस वर्ल्ड पंजाबण कंपीटिशन में मिस मोहाली भी रहीं। इसके बाद साल 2020 में राजनीति में आई और 2022 में विधायक भी बन गईं। एएपी सरकार ने उन्हें मंत्री बनाया।

पहली वफादारी देश के लिए, पार्टी के लिए नहीं

- **थरूर बोले-पार्टियां सिर्फ एक रास्ता हैं, देश को बेहतर बनाने का जरिया है**

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने कहा कि किसी भी नेता की पहली वफादारी देश के प्रति होनी चाहिए, पार्टी के प्रति नहीं। थरूर शनिवार को कोच्चि में शांति, सद्भाव और राष्ट्रीय विकास पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। थरूर ने कहा कि पार्टियां सिर्फ एक रास्ता हैं, देश को बेहतर बनाने का जरिया हैं। अगर देश ही नहीं बचेगा, तो पार्टियों का क्या फायदा। इसलिए जब देश की सुरक्षा का सवाल हो, तब सभी दलों को

मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा- कुछ लोग इसे पार्टी से गद्दारी समझ लेते हैं।

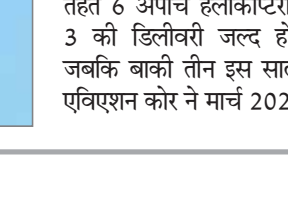

चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर शुरू किया डैम बनाना

बीजिंग (एजेंसी)। चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी (चीन में यारलुंग सांगपो) पर दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोपावर डैम बनाना शुरू कर दिया है। शनिवार को चीन के प्रधानमंत्री ली क्यांग ने इसकी शुरुआत

- **अरुणाचल सीएम बोले थे- ये हमारे लिए है वाटर बम**

की। रिपोर्ट के अनुसार, इस डैम प्रोजेक्ट को बीजिंग ने दिसंबर 2024 में मंजूरी दी थी। ये बांध चीन के न्यिंगची शहर में बनाया जा रहा है। इसकी कुल लागत करीब 167.8 अरब डॉलर (लगभग 12 लाख करोड़ रुपए) बताई गई है। यह डैम अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सटे न्यिंगची शहर में बनाया जा रहा है। इसे

इंडियन बॉर्डर के पास यह दुनिया का सबसे बड़ा बांध

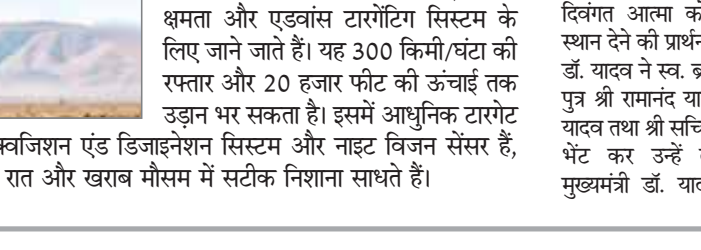

लेकर भारत और बांग्लादेश दोनों ने गहरी चिंता जताई है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इस बांध को भारत के लिए वाटर बम बताया था। करीब 2900 किलोमीटर लंबी ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उस पार तिब्बत के पठार पर 2057 किलोमीटर दूर तक पश्चिम की ओर बहती है और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। भारत के बाद ये बांग्लादेश में जाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, लेकिन भारत में प्रवेश से ठीक पहले ये नदी एक यू टर्न लेती है। यही वो इलाका है जहां चीन दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोपावर डैम बना रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसी साल 3 जनवरी को एक प्रेस ब्रीफिंग में इस बांध को लेकर आपत्ति जताई थी। भारत ने कहा था कि ब्रह्मपुत्र पर बांध बनाने से निचले राज्यों के हितों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। बांध से चीन को ब्रह्मपुत्र के जल प्रवाह को नियंत्रित करने की ताकत मिलेगी, जिससे अरुणाचल प्रदेश और असम में सूखा या बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। यह भारत की जल सुरक्षा नीति के लिए रणनीतिक खतरा है। बांध भूकंप-प्रवण क्षेत्र में बन रहा है, जिससे नदी पारिस्थितिकी, जैव विविधता और गाद प्रवाह पर नकारात्मक असर पड़ेगा। इससे भारत और बांग्लादेश में मछली पालन और खेती प्रभावित हो सकती है। ब्रह्मपुत्र पर निर्भर पूर्वोत्तर भारत के किसानों और मछुआरों की आजीविका खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि जल प्रवाह और गाद की कमी से मिट्टी की उर्वरता कम होगी। यह परियोजना भारत-चीन संबंधों में तनाव बढ़ा सकती है, खासकर अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास। जल डेटा साझा करने वाले समझौतों की समाप्ति ने स्थिति को और जटिल किया है।

रात हो या खराब मौसम ,एकदम सटीक निशाना

भारतीय सेना को जल्द मिलेंगे अपाचे हेलीकॉप्टर

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय सेना को अपाचे हेलीकॉप्टरों का पहला जत्था 22 जुलाई को मिलने की उम्मीद है। इसमें 15 महीने से अधिक की देरी पहले ही हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर पश्चिमी सीमा (पाकिस्तान-अफगानिस्तान) पर सेना की मारक क्षमता को बढ़ाने की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, 2020 में अमेरिका के साथ 600 मिलियन डॉलर का सौदा हुआ। इसके तहत 6 अपाचे हेलीकॉप्टरों में से पहले 3 की डिलीवरी जल्द हो सकती है, जबकि बाकी तीन इस साल के अंत तक पहुंच जाएंगे। सेना के एविएशन कोर ने मार्च 2024 में जोधपुर में पहली अपाचे स्क्वाड्रन तैयार की थी, लेकिन हेलीकॉप्टर न होने के कारण यह स्क्वाड्रन बिना उपकरणों के थी। रिपोर्ट के मुताबिक, सप्लाई चेन में रुकावटों

और तकनीकी समस्याओं के कारण डिलीवरी दिसंबर 2024 तक टल गई, जो मई-जून 2024 में होनी थी। इस देरी से पश्चिमी मोर्चे पर बढ़ते खतरे के बावजूद सेना ने तत्परता में कोई कमी नहीं छोड़ी। अपाचे हेलीकॉप्टर अपनी चपलता, मारक क्षमता और एडवांस टारगेंटिग सिस्टम के लिए जाने जाते हैं। यह 300 किमी/घंटा की रफ्तार और 20 हजार फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसमें आधुनिक टारगेट एक्विजिशन एंड डिजाइनेशन सिस्टम और नाइट विजन सेंसर हैं, जो रात और खराब मौसम में सटीक निशाना साधते हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्व. ब्रम्हानंद यादव को पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विदेश यात्रा से लौटने के बाद नई दिल्ली से सीधे रीवा पहुंचकर अपने ससुर स्वर्गीय श्री ब्रम्हानंद यादव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रीवा में संजय नगर में स्व. ब्रम्हानंद यादव के आवास पर पहुंचकर परिजन से भेंटकर सांत्वना दी तथा ईश्वर से दिवंगत आत्मा को श्री चरणों में स्थान देने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्व. ब्रम्हानंद यादव के पुत्र श्री रामानंद यादव, श्री सदानंद यादव तथा श्री सच्चिदानंद यादव से भेंट कर उन्हें ढाढ़स बंधाया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की धर्मपत्नी

श्रीमती सीमा यादव भी साथ थी। इस अवसर पर विधायक श्री नागेन्द्र सिंह, श्री सिद्धार्थ तिवारी, श्री नरेन्द्र प्रजापति एवं जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती नीता कोल तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

तीन आरोपियों की जमानत के बाद राजा के परिवार की आत्महत्या की चेतावनी

● राजा के भाई का आरोप साक्ष्य मिटाने के लिए आरोपियों की जमानत

इंदौर। ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में शिलांग पुलिस ने लोकेंद्र तोमर और बलवीर के बाद प्रॉपर्टी ब्रोकर शिलोम जेम्स को भी जमानत दे दी। राजा के भाई विपिन ने आरोप लगाया कि यह सब साक्ष्य छुपाने के लिए किया जा रहा है। शिलोम की जमानत की सूचना के बाद राजा की मां उमा बाई की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया। राजा के पूरे परिवार ने सामूहिक आत्महत्या की चेतावनी दी है इससे पहले सिक्युरिटी गार्ड बलवीर और बिल्डिंग मालिक लोकेन्द्र सिंह तोमर को जमानत मिली थी। तीनों आरोपियों को जमानत मिलने से राजा के परिवार को आशंका है कि उनके बेटे को न्याय नहीं मिल पाएगा। इसके चलते रघुवंशी परिवार ने सामूहिक आत्महत्या की चेतावनी दी। आंसुओं में डूबी मां उमा रघुवंशी ने कहा कि राजा मेरी बहू के सपनों में आया था, उसने कहा था वो लौटेगा। लेकिन, जब से सुना कि जिन लोगों ने साक्ष्य मिटाए, उन्हें जमानत मिल गई, मेरा कलेजा कांप गया। मुझे अब भी कोई डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला, न कोई कॉल आया, न कोई जवाब। मैं खुद शिलांग जाऊंगी, बेटे के लिए न्याय मांगूंगी।

राजा के भाई ने लगाए आरोप: राजा के भाई विपिन ने कहा कि जिन तीन आरोपियों को जमानत मिली है, उन्हें गोविंद की शह प्राप्त है। उनका दावा है कि गोविंद की योजना राज और सोनम की शादी कराने की है और इसके लिए वह आरोपियों को बचा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने डेढ़ महीने से अधिकारियों से डेथ सर्टिफिकेट की मांग की, लेकिन अब तक कुछ नहीं मिला। आरोपी एक-एक कर छूट रहे हैं, हमें डर है कि वे छूटकर हमारे परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमारी जान को खतरा है।

शिलांग सरकार होगी जिम्मेदार: इस मामले में राजा के बड़े भाई सचिन ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बाकी आरोपी भी छूट गए, तो हम पूरा परिवार आत्महत्या कर लेंगे। इसकी जिम्मेदार शिलांग सरकार की होगी। राजा की हत्या के बाद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। केस डायरी तक कोर्ट नहीं पहुंची और आरोपी एक के बाद एक बाहर आ रहे हैं, जो समझ से परे है।

इंदौर-मुंबई के बीच चलेगी 23 जुलाई से मध्य प्रदेश की पहली तेजस ट्रेन

सप्ताह में 3 दिन चलेगी, 21 जुलाई से बुकिंग शुरू, किराया ज्यादा

इंदौर। मुंबई और इंदौर के बीच 23 जुलाई से सुपरफास्ट तेजस ट्रेन चलाई जाएगी। पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और विशेष रूप से यात्रा की मांग को ध्यान में रखते हुए मुंबई सेंट्रल और इंदौर स्टेशनों के बीच विशेष किराए पर सुपरफास्ट तेजस स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है।

तेजस ट्रेन, भारतीय रेलवे की एक अर्ध-उच्च गति वाली, पूरी तरह से वातानुकूलित ट्रेन है, जो आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसमें स्वचालित दरवाजे, आरामदायक सीटें, एलसीडी स्क्रीन, वाई-फाई और बायो-वैक्यूम शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह देश की पहली निजी और कॉर्पोरेट ट्रेन है, जिसका संचालन आईआरसीटीसी करती है।

इसकी बुकिंग 21 जुलाई से शुरू होगी। रेलवे सूत्रों के अनुसार, इंदौर से मुंबई के बीच तेजस ट्रेन चलाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस मार्ग पर विशेष किराए के तहत इसका संचालन शुरू किया जाएगा। पश्चिम रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार, यह स्पेशल ट्रेन (संख्या 09085) प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को मुंबई सेंट्रल से रात 11.20 बजे प्रस्थान करेगी। अगले दिन दोपहर 1 बजे इंदौर पहुंचेगी। वहीं इंदौर से यह स्पेशल ट्रेन

(संख्या 09086) प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को इंदौर से शाम 5 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 7.10 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी। रेलवे सूत्रों के अनुसार, इंदौर से मुंबई के मध्य चलने वाली इन स्पेशल ट्रेन का संचालन 23 जुलाई से 30 अगस्त तक किया जाएगा। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, सूरत, वडोदरा, दाहोद, रतलाम और उज्जैन स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, एसी 2-टियर एवं एसी 3-टियर कोच होंगे। ट्रेन संख्या 09085 एवं 09086 की बुकिंग 21 जुलाई से सभी पीआरएस काउंटरों एवं आईआरसीटीसी वेबसाइट पर प्रारंभ होगी।

किराया अभी तय नहीं

रेलवे सूत्रों के अनुसार, इंदौर-मुंबई तेजस स्पेशल का किराया फिलहाल तय नहीं हुआ। लेकिन, यह 1100 से 3300 रुपए तक हो सकता है। इसमें बेस फेयर, डायनेमिक फेयर, आरक्षण शुल्क और लागू रियासतें शामिल होंगी। इंदौर से मुंबई के बीच एग्जीक्यूटिव चेयर कार का किराया लगभग 2484 रुपए और एसी चेयर कार का किराया लगभग 1390 रुपए हो सकता है। मुंबई से इंदौर के बीच एग्जीक्यूटिव चेयर कार का किराया करीब 2454 रुपए और एसी चेयर कार का 1394 रुपए रहने की संभावना है। हालांकि यह सभी किराए संभावित हैं और इनमें बदलाव संभव है।

दुरंतो से महंगा है तेजस का किराया

इंदौर-मुंबई के बीच चलने वाली तेजस स्पेशल का किराया वर्तमान में इसी मार्ग पर चल रही दुरंतो एक्सप्रेस से अधिक है। इंदौर-दुरंतो में फिलहाल सेकंड सिटिंग का किराया 460 रुपए, एसी इकोनॉमी का 2070 रुपए, थर्ड एसी का 2205 रुपए, सेकंड एसी का 2975 रुपए और फर्स्ट एसी का किराया 3670 रुपए है। वहीं तेजस स्पेशल ट्रेन के किराए निर्धारण का अधिकार आईआरसीटीसी को होगा, जो आवश्यकता अनुसार किराया बढ़ा सकती है। यदि ट्रेन देरी से चलती है तो आईआरसीटीसी यात्रियों को रिफंड भी देगा।

10 हजार का इनामी हथियार तस्कर गिरफ्तार

इंदौर। शहर में अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत क्राइम ब्रांच पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 10 हजार रुपए के इनामी बदमाश आजाद सिंह भाटिया को गिरफ्तार किया, जो जंगलों में देशी पिस्टल और कट्टे बनाकर इंदौर में ऊंचे दामों पर सप्लाई करता था। इससे पहले उसके साथी हिरमल चौहान की गिरफ्तारी के दौरान 10 देशी पिस्टल, दो जिंदा राउंड, मोबाइल और मोटरसाइकिल बरामद की गई थी। पूछताछ में हिरमल ने खुलासा किया था कि ये हथियार आजाद सिंह बनाता था। आजाद सिंह घटना के दिन से ही फरार था। उसे पकड़ने के लिए पुलिस उपायुक्त (अपराध) द्वारा इनाम घोषित किया गया था। मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड लिया है और अब उससे पूछताछ कर अन्य तस्करों और नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है। कार्रवाई थाना अपराध शाखा में दर्ज अपराध धारा 25 (1) (अअ) 27 आर्म्स एक्ट के तहत की गई।

11 कॉलोनियों के प्लॉट राजसात होंगे

इंदौर। ओएस्टर, ज्ञानशीला, ट्रेजर फेंटेसी सहित 11 कॉलोनियों के प्लॉट अब राजसात किए जाएंगे। इन कॉलोनाइजर द्वारा निर्धारित तीन वर्ष की समय सीमा में विकास कार्य पूर्ण नहीं किए गए, जबकि 6 साल से अधिक समय बीत चुका है। प्रशासन ने एक सप्ताह पहले ही 17 कॉलोनियों को नोटिस थमाया था। अब नोटिस के जवाब के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अपर कलेक्टर गौरव बेनल ने बताया कि लापरवाही बरतने वाली कॉलोनियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया गया है। अब तक 7 कॉलोनियों के प्लॉट राजसात किए जा चुके हैं।

पेट्रोल पंप के टैंक में भंडारित डीजल में पानी मिला, पंप सील किया गया

● जांच के दौरान डीजल के स्टॉक में 451 लीटर का अंतर मिला

इंदौर। जिले में उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्वक एवं सही माप से डीजल-पेट्रोल सहित अन्य ईंधन उपलब्ध कराए जाने के लिए अभियान चलाकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। अपर कलेक्टर गौरव बेनल के मार्गदर्शन में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक टैंक में भंडारित डीजल में पानी पाये जाने पर पेट्रोल पंप को सील कर दिया। इस पंप द्वारा नोजल से उपभोक्ताओं को मानक मात्रा से कम

डीजल प्रदाय किया जाता था। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा बार-बार दिये गये निर्देशों के बावजूद भी पंप पर उपभोक्ताओं की सुविधा के लिये पीयूसी सेंटर भी स्थापित नहीं किया था। जिला आपूर्ति नियंत्रक एमएल मारू ने बताया कि राऊ स्थित पेट्रोल पंप 'यूनाइटेड ऑटो सर्विस' की जांच पम्प के प्रबंधक प्रिंस पिता प्रीतपाल टुटेजा की उपस्थिति में खाद्य विभाग के अमले द्वारा की गई। जांच के दौरान डीजल के स्टॉक में 451 लीटर का अंतर होना पाया गया। ऑयल कंपनी द्वारा छूट मानक स्तर की सीमा से अधिक पाया गया। डीजल के नोजल से 5 लीटर की माप में मात्रा का परीक्षण करने पर 5 लीटर मानक ईंधन प्रदाय करना नहीं पाया गया एवं लगभग 20 एमएल तक कम प्रदाय किया जाना पाया गया। डीजल के भूमिगत टैंक में संग्रहित डीजल में वाटर टेस्टिंग पेस्ट द्वारा परीक्षण करने पर 2 सेंटीमीटर कुल 22 लीटर पानी मिला होना पाया गया। मौके पर पम्प परिसर में पीयूसी सेंटर का संचालन होना नहीं पाया गया। मौके पर उपभोक्ताओं को पेट्रोल में इथेनॉल मिक्स होने संबंधी जानकारी का प्रदर्शन होना नहीं पाया गया। मौके पर फर्स्ट एड बॉक्स में पर्याप्त दवाइयां होना नहीं पायी गई। उपरोक्त अनियमितताएं कारित करने से यूनाइटेड ऑटो सर्विस (आईओसी कंपनी द्वारा संचालित पेट्रोल पम्प) राऊ के प्रबंधक से भूमिगत टैंक में उपलब्ध 890 लीटर डीजल (एचएसडी) जिसकी बाजार कीमत कुल 81 हजार 909 रुपये आंकी गई है तथा उपभोक्ताओं के हित में पेट्रोल पंप को न्यायालय के आगामी आदेश तक सील कर दिया गया है।

काली बिल्लोद में शासकीय भूमि पर अवैध कॉलोनी काटी, अवैध निर्माण

शासकीय भूमि का लगाया बोर्ड, अवैध कब्जा हटाना अभी बाकी

इंदौर। जिले के बेटमा में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा हटाने के लिए स्थानीय प्रशासन ने बोर्ड लगाया। लेकिन, अभी भी अवैध कब्जा हटाना बाकी है। प्रशासन ने भूमि पर अपना स्वामित्व दर्शाने के लिए बोर्ड तो लगा दिया है, लेकिन अभी भी कुछ लोगों ने उस भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है, जिसे हटाया जाना है। शासकीय भूमि पर बोर्ड लगाने का प्रशासन का मुख्य उद्देश्य जनता को यह जानकारी देना है कि यह भूमि सरकारी है और इस पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा मान्य नहीं होगा। बेटमा के समीप ग्राम पंचायत काली बिल्लोद में वैध कॉलोनी कल्याण संपत के पीछे पीथमपुर सेक्टर नंबर-3 इंडोरामा के समीप ग्राम सुलावड़ के भूमाफिया ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर जमीन खरीदकर उस पर अवैध कॉलोनी काट दी। इसी से सटी हुई शासकीय भूमि पर भी अवैध कब्जा कर अवैध निर्माण कर दिया।

इसकी शिकायत पर देपालपुर एसडीएम राकेश मोहन त्रिपाठी ने गत दिनों निरीक्षण किया, तो पाया कि भूमाफिया द्वारा निजी जमीन की रजिस्ट्री करवा कर लोगों को शासकीय भूमि पर अवैध कब्ज़ा दिया गया। जिस पर एसडीएम ने बेटमा के नायक तहसीलदार

निधि राजपूत धाकड़ को उक्त भूमि पर शासकीय भूमि का बोर्ड लगवाने और वहां पर अतिक्रमण कर रहे लोगों की रजिस्ट्री की कॉपी लेकर उनके खिलाफ अवैध अतिक्रमण का कैसे बनाने और उन्हें नोटिस देने के निर्देश दिए थे। जिस पर बेटमा तहसीलदार के निर्देश पर कस्बा पटवारी शरद शर्मा द्वारा उक्त भूमि ग्राम काली बिल्लौद के सर्व क्र . 173, 198, 199, 200 की भूमि शासकीय भूमि है इस पर अवैध निर्माण एवं क्रय विक्रय वर्जित है का गुरुवार को बोर्ड लगाया गया है।

पूर्व पटवारी और अधिकारी संदिग्ध: कालीबिल्लौद के सरपंच ने और रहवासियों ने पूर्व अधिकारियों पर कई बार लापरवाही के आरोप लगाहैं। जानकारी के अनुसार काली बिल्लोद के सरपंच ने आठ माह पूर्व पटवारी, तहसीलदार और एसडीम को पंचायत से लेटर जारी कर कई बार शिकायत की पर कोई संज्ञान न लेने के कारण भू माफियाओं के हौसले बुलंद होते गए और भूमाफिया करोड़ों की शासकीय भूमि निगल गए जिससे पटवारी, तहसीलदार की भूमिका संदेहास्पद है। सूत्रों के अनुसार काली बिल्लोद के पूर्व पटवारी और भू माफिया की उस समय अच्छी जुगल बंदी हुई थी अगर जांच की जाएगी तो कई मामले खुल कर सामने आएंगे।

दोस्तों के साथ पार्टी करने निकली युवती की सड़क दुर्घटना में मौत

ट्रक की टक्कर से गई आस्था की जान, दोस्त गंभीर घायल

इंदौर। शनिवार रात इंदौर के तिल्लौर क्षेत्र में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक साफ्टवेयर इंजीनियर युवती आस्था सिंह की मौत हो गई। आस्था अपने छह दोस्तों के साथ पार्टी के लिए ढाबे जा रही थी। वह एक दोस्त जितेंद्र की बाइक पर पीछे बैठी थी। तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में आस्था गंभीर रूप से घायल हुई और एमवाय अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बाइक चला रहा रतलाम निवासी जितेंद्र भी गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में भर्ती है। आस्था मूलतः उत्तर प्रदेश के अकबरपुर (कानपुर के पास) की रहने वाली थी। वह चार महीने पहले ही इंदौर आई थी और केसरबाग क्षेत्र में रहकर एक सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी कर रही थी।

शनिवार को उसने दोस्तों के साथ ढाबे पर पार्टी करने का प्लान बनाया था। सभी दोस्त अलग-अलग बाइक पर निकले थे, लेकिन हादसे के वक्त आस्था और जितेंद्र की बाइक सबसे पीछे रह गई थी। अंधेरे और अचानक हुई टक्कर का फायदा उठाकर ट्रक चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक और चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आस्था के अन्य दोस्त भी ट्रक का नंबर नहीं देख पाए, जिससे तलाश में कठिनाई आ रही है। हादसे की खबर मिलते ही आस्था के परिजन कानपुर से इंदौर रवाना हो गए हैं।

बच्चों की अहिल्या माता का लोकार्पण

इंदौर। श्री अहिल्या उत्सव समिति द्वारा मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति सभागार में लोकमाता अहिल्या की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर अरविंद जवलेकर की कृति 'बच्चों की अहिल्या माता' का लोकार्पण किया गया। मुख्य अतिथि उदयसिंह राजे होल्कर व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने अहिल्या माता के कृतित्व और जनकल्याण पर प्रकाश डाला। प्रेस क्लब अध्यक्ष अरविंद तिवारी ने कृति को बच्चों के लिए प्रेरणादायी बताया। कृति पर संक्षिप्त चर्चा विनीता धर्म ने की। कार्यक्रम में अनेक साहित्यकार व गणमान्यजन उपस्थित रहे।अरविंद जवलेकर को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया।

राऊ तहसील कार्यालय शुरू, इंदौर नहीं जाना पड़ेगा

राऊ। लंबे समय से प्रतीक्षित राऊ तहसील कार्यालय का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती, विधायक मधु वर्मा,जिलाध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा, भाजयुमो अध्यक्ष मनोज ठाकुर,महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष किरण सूर्यवंशी,नगर परिषद अध्यक्ष पप्पी विजय पाटीदार समाज सेवी किशोर चौधरी समेत कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। एसडीएम गोपाल वर्मा और तहसीलदार याचना दीक्षित के कार्यभार ग्रहण के साथ ही राऊ क्षेत्र के ग्रामीणों को अब राजस्व संबंधी कार्यों के लिए इंदौर नहीं जाना पड़ेगा। कार्यक्रम में राऊ विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों के सरपंच और ग्रामीणों ने भी भाग लिया। इस नए तहसील कार्यालय से क्षेत्रीय कार्यों को गति मिलेगी और नागरिकों को समय व सुविधा दोनों का लाभ मिलेगा। ग्रामीणों ने इसे बड़ी राहत बताया।

महिलाओं के लिए निःशुल्क लर्निंग लाइसेंस शिविर

इंदौर। महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए इंदौर नगर निगम, पुलिस कमिश्नरेट और आरटीओ विभाग के संयुक्त प्रयास से 'लाइसेंसधारी,सशक्त नारी' अभियान शुरू किया गया है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव के नेतृत्व में ट्रैफिक मित्र महाअभियान के अंतर्गत कल रविवार को शहर के सभी 22 ज़ोन कार्यालयों में निःशुल्क लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस शिविर आयोजित हुए। यह शिविर सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक लगाए गए। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को ड्राइविंग के लिए प्रेरित करना और सड़क सुरक्षा में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है। पंजीकरण व जानकारी के लिए वार्ड पार्षद कार्यालय से संपर्क किया गया।

सुपर से भी ऊपर इंदौर, देश को सिखाएगा सफाई का पाठ

स्वच्छ सुपर लीग में प्रथम, वाराणसी की भी जिम्मेदारी

इंदौर। स्वच्छता में देशभर में अव्वल इंदौर ने एक बार फिर इतिहास रचते हुए स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में स्वच्छ सुपर लीग की कड़ी प्रतिस्पर्धा में पहला स्थान प्राप्त किया है। राष्ट्रपति द्वारा नई दिल्ली में दिए गए इस सम्मान के बाद, इंदौर लौटते ही महापौर पुष्यमित्र भार्गव, आयुक्त शिवम वर्मा और स्वच्छता टीम का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। स्वच्छता रथ, बैंड-बाजों और जन समर्थन के साथ राजवाड़ा तक पहुंचे दल का गर्मजोशी से अभिनंदन किया गया। महापौर ने मां अहिल्या की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर, सफाई मित्रों और जनता को इस सफलता का असली भागीदार बताया। उन्होंने घोषणा की कि सफाई मित्रों को अब स्वास्थ्य के लिए रू. 1000 प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि जब प्रधानमंत्री ने लाल किले से स्वच्छता का आह्वान किया, तब इंदौर ने इसे जन आंदोलन बना दिया और 7 बार देश में नंबर वन बना। वहीं भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने जानकारी दी कि इंदौर को अब वाराणसी की सफाई की जिम्मेदारी भी मिली है। आयुक्त शिवम वर्मा ने कहा कि इंदौर अपने सफाई के नवाचारों से अन्य शहरों को भी स्वच्छता का पाठ पढ़ाएगा। यह सफलता जनता, मीडिया, निगम कर्मचारियों और सफाई मित्रों के सतत प्रयासों का परिणाम है। इंदौर अब स्वच्छता का रोल मॉडल बनकर देश को राह दिखाएगा।

अस्पतालों में दुर्घटना पीड़ितों के डेढ़ लाख तक मुफ्त इलाज की योजना लांच ही नहीं

● अस्पतालों में क्लेम संबंधित स्कीम पोर्टल ही अपलोड नहीं हुआ

इंदौर। केंद्र और राज्य सरकार सहित शासन और प्रशासन ने सड़क दुर्घटना में घायलों के 1 लाख 50 हजार रुपये तक मुफ्त इलाज वाली योजना का प्रचार-प्रसार तो बहुत किया, मगर इस योजना का लाभ अभी तक किसी भी घायल को नही मिल पा रहा है। अब तक यह योजना सिर्फ कागजों या डिजिटल फाइलों पर ही मौजूद है। इस वजह से अस्पताल वाले और घायल दोनों परेशान हो रहे हैं। यह खुलासा तब हुआ जब जिला स्वास्थ्य विभाग से यह जानकारी मांगी गई कि अभी तक कितने निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज वालों का सत्यापन किया है, तो अधिकारियों ने बताया कि उनके पास अभी तक एक भी मामला सत्यापन के लिए नहीं आया है । इसकी मुख्य वजह यह है कि तकनीकी कारणों के

चलते दुर्घटना पीड़ितों के लिए बनाई गई इस कैशलेस स्कीम और क्लेम से संबंधित पोर्टल अथवा वेबसाइट अभी तक लांच नहीं हो पाई।

परिजनों को समझाना मुश्किल

इस मामले में कुछ निजी अस्पतालों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सरकार ने सडक़ परिवहन मंत्रालय की इस योजना की मीडिया के माध्यम घोषणा तो पिछले जून माह में ही कर दी मगर दुर्घटना पीड़ितों के कैसलेश इलाज और क्लेम रूल्स रेग्युलेशन सम्बन्धित पोर्टल या वेबसाइट कम्प्यूटर पर अभी तक लोड नहीं हो रहा है। इस कारण उनके यहां जो भी दुर्घटना घायल इलाज के लिए आते हैं, उन्हें समझना मुश्किल हो जाता है।

मुफ्त इलाज के लिए इतना जरूरी: जिस नजदीकी अस्पताल में पीड़ित को ले जाया गया है। यदि वहां पीड़ित के इलाज के हिसाब से संसाधन नहीं हैं तो वहां उसकी प्राथमिक चिकित्सा कर वह दूसरे अस्पताल को भेजेगा। प्राथमिक चिकित्सा में जो भी खर्च हुआ। हॉस्पिटल प्रबंधन को उसे पेशेंट क्लेम पोर्टल पर दर्ज करना होगा। इसके इलाज के दौरान हॉस्पिटल प्रबंधन यह जांचेगा पीड़ित का आयुष्मान योजना से सम्बन्धित है या नहीं या अन्य किसी बीमा एजेंसी में बीमा है। यदि पीड़ित का बीमा नहीं है तो जिस वाहन से या सामने वाले वाहन का थर्ड पार्टी बीमा है कि नहीं, यह सारी जानकारी स्कीम पोर्टल पर दर्ज करना होगी ।

सत्यापन की जिम्मेदारी विभाग की

केंद्र सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय की इस योजना के अंतर्गत सडक़ दुर्घटना में घायलों का 1.50 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करना निजी अस्पतालों की जिम्मेदारी हैं। मतलब अब निजी अस्पताल घायलों का मुफ्त इलाज करने से मना नही कर सकते । इस योजना के अंतर्गत जिस अस्पताल में घायल का इलाज होता है, वहां जाकर स्वास्थ्य विभाग को घायल के इलाज का सत्यापन करना होता है मगर 18 जुलाई तक स्वास्थ्य विभाग के पास सत्यापन का एक भी मामला नहीं है। इस एक्सीडेंटल कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम के अंतर्गत दुर्घटना पीड़ित को नजदीकी हॉस्पिटल तक पहुंचाने वालों को 25,000 रुपये तक कि प्रोत्साहन राशि देने की व्यवस्था है मगर यदि एक से ज्यादा लोग पीड़ित को अस्पताल लेकर पहुंचे है तो यह राशि सभी मे सदस्यों के हिसाब से बंट जायगी।

संपादकीय

स्वच्छता में मप्र का डंका!

वर्ष 2024 के स्वच्छ सर्वेक्षण में मप्र के 8 शहरों को पुरस्कृत होना निश्चय ही गौरव की और नागरिकों को पहले की तुलना में ज्यादा जिम्मेदार बनने की बात है। मप्र के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ठीक ही कहा है कि यह देश में स्वच्छता के क्षेत्र में मप्र का डंका है। बीते गुरुवार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुरस्कृत शहरों को इनाम बांटे। ये पुरस्कार केन्द्रीय शहर आयोजना मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं। इसके पहले एक टीम सभी राज्यों के शहरों का स्वच्छ सर्वेक्षण करती है। जो विभिन्न मानदंडों के आधार पर शहर को नंबर देती है। राज्य की आर्थिक राजधानी इंदौर तो मानो अब देश में स्वच्छता का मॉडल ही बन गया है। इसके लिए इंदौरवासियों और प्रशासन को बधाई। इस बार केन्द्र सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण में दो श्रेणियां बनाई थीं। पहली श्रेणी सुपर लीग में उन शहरों को शामिल किया गया, जो दो साल से लगातार स्वच्छता में टॉप-3 में आ रहे थे। इसी में हमेशा की तरह इंदौर टॉप पर रहा। जबकि दूसरी श्रेणी की सामान्य स्वच्छता रैंकिंग के स्वच्छतम शहरों में भोपाल को दूसरा और जबलपुर को पांचवां स्थान मिला। 3 से 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में महाकाल की नगरी उज्जैन तो 20 हजार से कम जनसंख्या वाले शहरों में बुधनी सर्वश्रेष्ठ शहर रहा। देवास, जबलपुर, ग्वालियर, शाहगंज भी पुरस्कृत 50 हजार से तीन लाख जनसंख्या वाले शहरों में देवास को प्रथम तथा 20 हजार से कम जनसंख्या वाले शहरों में शाहगंज को तृतीय पुरस्कार मिला। इसी प्रकार सफाई मित्र सुरक्षित शहर की श्रेणी में जबलपुर और ग्वालियर को प्रोमिसिंग शहर (स्टेट अवार्ड) श्रेणी में पुरस्कृत किया गया। प्रदेश की ओर से नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के साथ संबंधित निकायों के महापौर या निकाय अध्यक्ष और अधिकारियों ने पुरस्कार प्राप्त किए। इनके अलावा प्रदेश के 203 शहरों को स्टार रेटिंग प्रमाणीकरण मिला, जिसमें विगत वर्ष के 157 शहरों से 12 प्रतिशत अधिक शहरों ने स्टार रेटिंग प्राप्त की। सर्वेक्षण में भोपाल, इंदौर, जबलपुर को सात स्टार, देवास, रीवा और सतना को पांच स्टार रैंक प्राप्त हुई है। साथ ही प्रदेश के 36 शहरों को तीन स्टार और 161 शहरों को एक स्टार रैंक मिली है। एक और अच्छी बात है कि स्वच्छ सर्वेक्षण में अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ भारत के नए स्वच्छ शहर के रूप में उभरे हैं। जबकि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 34 शहरों को भविष्य में बेहतर स्वच्छता प्रदर्शन करने के संभावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही सरकार ने स्वच्छ शहर साझेदारी शुरू की है, जिसके तहत शीर्ष स्वच्छ शहर, कमतर प्रदर्शन करने वाले शहरों को परामर्श देंगे। जहां तक इंदौर की बात है तो सफाई अब इंदौरवासियों की आदत बन चुकी है, जोकि भारत जैसे देश में असाधारण बात है। अपने शहर को साफ रखने को लेकर यहां के लोग अब हर नागरिक जैसे चौकन्ना दिखता है, वह अद्भुत है। जबकि भोपाल को दूसरी श्रेणी में दूसरा स्थान जरूर मिला है, लेकिन स्वच्छता का स्तर दैनंदिन व्यवहार में वैसा नहीं दिखता, जैसा कि होना चाहिए। हकीकत में प्रदेश की राजधानी में स्वच्छता को लेकर सतर्कता केवल तभी ज्यादा दिखाई पड़ती है, जब स्वच्छ सर्वेक्षण टीम यहां का दौरा करती है, जबकि यह जागरूकता साल भर दिखनी चाहिए। बावजूद इसके पहले की तुलना में भोपाल ज्यादा स्वच्छ दिखता है। मोदी सरकार द्वारा देश को शहरों में स्वच्छता की प्रतिस्पर्धा उस आरोप का सकारात्मक जवाब है, जिसमें कहा जाता है कि भारत के शहर और भारतीय बहुत गंदे रहते हैं। इस अभियान की वास्तवित सफलता तब होगी, जब बिहार जैसे राज्य का कोई शहर भी पुरस्कार पाएगा।

नजरिया

रघु ठाकुर

लेखक समाजवादी चिंतक हैं।

इजराइल और हमास युद्ध

मैं कई बार पूर्व में भी लिख चुका हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई प्रभावी भूमिका नहीं बची। इस्लामिक देश भी कई कारणों से बंटे हुए हैं। वैसे तो अमेरिका हमले को रूस, चीन, पाक, सऊदी अरब और ओमान ने अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताकर निंदा की है। परंतु यह निंदा फिलहाल सिया और सुन्नी के मध्य विभाजित है। पाकिस्तान जो अमेरिकी मदद के समर्थन पर जिंदा है। वह वैसे भी अपनी जीर्ण क्षीण अर्थव्यवस्था और आंतरिक जनविद्रोह के चलते कुछ मदद करने की स्थिति में नहीं है। उसने चीन को बन रोड वन बेल्ट के लिये अपना भूभाग उपलब्ध कराया है परंतु चीन का यह स्वप्नदर्शी योजना अभी केवल अमूर्तरूप में है। सऊदी अरब आदि देशों के मुखिया भी स्वतः युद्ध के लड़ने के पक्ष में नहीं है। चीन की जमीनी दूरी ईरान से इतनी अधिक है कि चीन भी कोई वास्तविक मदद पहुँचाने की स्थिति में नहीं है और यह युद्ध होता है तो रूस व चीन की इसमें भौतिक व वास्तविक भागीदारी नगण्य होगी, चीन की तो बिल्कुल ही प्रतीकात्मक।

इजराइल और हमास के बीच चल रहे दीर्घकालिक युद्ध के बीच इजराइल ने अचानक एक नया मोड़ लिया और ईरान पर मिसाईल अटैक किया। आरंभ में ईरान उत्तर देगा ऐसा उसने कहा, परंतु दुनिया में एक धारणा थी कि इजराइल सैन्य शक्ति के रूप में बहुत शक्तिशाली है अतः ईरान का प्रति उत्तर केवल शाब्दिक रहेगा। परंतु दो या तीन दिन के बाद ईरान ने हजारों ड्रोन व मिसाईलों के माध्यम से इजराइल पर हमला किया और इजराइल का तथाकथित आयरन ड्रोन जिसे ब्रह्म कवच माना जाता था और यह भी माना जाता है कि दुनिया की कोई भी मिसाइल इसको भेद नहीं सकती, वह नष्ट हुआ। ईरान को यद्यपि जनहानि तो कम हुई पर सांपत्तिक हानि अधिक हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने यह सार्वजनिक रूप से कहा कि अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेगा, परंतु इजराइल के ऊपर सफल प्रति आक्रमण और खतरे को समझकर ट्रंप ने तत्काल पैंतरा बदला तथा ईरान और उसके परमाणु केंद्रों पर बंकर मिसाइल से हमला किया। जब आरंभ में इजराइल ने ईरान पर हमला किया और यह समाचार आये थे कि ईरान के परमाणु ठिकानों को उनकी मिसाईलें नष्ट नहीं कर सकी क्योंकि वह बंकरों के अंदर है। परंतु अमेरिकी हमले के बाद ईरान के कई परमाणु ठिकाने नष्ट हुए या क्षतिग्रस्त हुये और ईरान के सेना मंत्री ने इसे स्वीकार किया। हालाँकि यह भी कहा कि जो संवर्धन यूरेनियम परमाणु बम बनाने में इस्तेमाल होता है उसे ईरान ने पहले ही सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दिया था, इसलिये वह नष्ट होने से बच गया। यह भी बताया गया कि इस परमाणु बम का ईंधन 270 फुट गहरे बंकरों में रखा गया है और अमेरिकी मिसाईल का वहाँ तक पहुँचना संभव नहीं है। अमेरिकी हमले के बाद इस दुनिया को खतरा लग रहा था कि अब विश्व युद्ध की कगार पर दुनिया है और ईरान अमेरिका पर हमला करेगा। परंतु ईरान ने सीधे अमेरिका पर तो हमला नहीं किया बल्कि अमेरिका के दूसरे देशों के समुद्री द्वीपों पर बनाये गये एक सामरिक केंद्र कतर पर हमला किया। हालाँकि वह कोई प्रभावी सिद्ध नहीं हुआ। अमेरिका ने यह भी कहा कि कोई क्षति नहीं हुई है और कहा कि अब ईरान परमाणु संधि वार्ता को अंतिम रूप दे वर्ना पुनः हमले होंगे।

इस घटनाक्रम को दुनिया का एक हिस्सा इस रूप में देख रहा था कि शायद अब ईरान अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों की निगरानी में परमाणु केंद्रों की जांच के लिये तैयार हो जायेगा और अमेरिका का जो लक्ष्य है कि ईरान परमाणु अस्त्र न बना सके, वह हासिल हो जायेगा। परंतु 2 जुलाई 25 को ईरान के राष्ट्रपति ने जिस निर्णय की घोषणा की है कि ईरान, अमेरिका व अन्य देशों के बीच परमाणु संधि से हट गया है याने अब पहले जो समस्या संधि के पालन की थी,अब अमेरिकी हमले के साथ ईरान संधि से ही हट गया। रूस ने ईरान का खुलकर समर्थन किया है और ईरान को आवश्यक हथियार, मिसाईलें आदि देने की घोषणा की है। यहाँ तक की रूसी सिक्युरिटी कौंसिल के डिप्टी चेयरमैन मेदवेदेव ने कहा कि रूस वारहेड देगा और ईरान का एटमी प्रोग्राम तेजी से बढ़ेगा। रूस के समर्थन के बाद ही ईरान ने परमाणु संधि से बाहर हटने का ऐलान किया है। हालांकि चीन ने ईरान की कोई विशेष मदद नहीं की, शिवाय राजनैतिक समर्थन के। शायद चीन, ईरान, रूस की निकटता से भी सावधान है। क्योंकि रूस व चीन के बीच भी सीमा विवाद है। वैसे भी दुनिया में कोई किसी का स्थायी साथी नहीं है, वैसे चीन, अमेरिका, इजराइल के खिलाफ है पर गाजा में इजराइल ने जो पुनर्निर्माण का काम शुरू किया है, उसमें चीनी कंपनी को ठेका दिया है तथा 6000 चीनी कर्मचारी वहाँ काम कर रहे हैं, व्यापार में इजरायल व चीन साथ हैं। यूक्रेन और रूस के बीच में जो लंबा युद्ध चल रहा है उसमें भी रूस यूरोप और अमेरिका के खिलाफ ही एक प्रकार से अप्रत्यक्ष युद्ध लड़ रहा है। अमेरिका युद्ध बंदी के नाम पर ब्लैकमेलिंग करना चाहता है और अपने आर्थिक, सामरिक हितों को और अपनी सैन्य श्रेष्ठता को कायम रखना चाहता है। पिछले लगभग दो दशकों से

अमेरिका ने सीधे तौर पर किसी युद्ध में काम नहीं किया था परंतु यह इतने समय के बाद कि घटना है कि जब अमेरिका सीधा युद्ध में कूदा है। दुनिया में हथियार संपन्न देशों की दो धुरी बन रही है। एक में चीन, रूस और ईरान हैं और दूसरे में अमेरिका, इजराइल, यूक्रेन और यूरोप के फ्रांस, जर्मनी आदि देश शामिल हैं। इसी बीच में रूस ने पुनः एक बार यूक्रेन पर भारी हमला बोला और इससे बड़ी संख्या में जन-धन की हानि हुई है, यूक्रेन ने भी रूस के काफी अंदर जाकर परमाणु ठिकानों पर हमला किया। अब अगर ईरान परमाणु हथियार बनाता है तो यह अमेरिका, इजराइल और यूरोप के देशों के लिये एक बड़ा खतरा है। ईरान ने इजराइल पर हमले में मिसाईल का इस्तेमाल किया था वह 8600 प्रति किमी की रफ्तार से चलने वाली थी। जिसमें 1500 किग्रा वारहेड होता है और 1500 किमी की दूरी तक वह मार कर सकती है। यह भी खबर आई थी कि ईरान ने जो हमला इजराइल पर किया था उसके बाद, उसके पास वारहेड की कमी हुई। याने संचित बारूद का भंडार घट गया, परंतु अब रूस उसकी क्षतिपूर्ति के लिये सामने आया है और इससे ईरान की सामरिक शक्ति पुनः खड़ी हो सकती। दूसरा एक आर्थिक पक्ष भी है कि 33 किमी होर्मुज समुद्री गलियारा, यह युद्ध का क्षेत्र बनेगा। क्योंकि दुनिया का कोई 26 प्रतिशत कच्चा तेल इसी गलियारे से जाता है। अमेरिका की भी बड़ी सप्लाई इस गलियारे से होती है। अगर ईरान इस गलियारे को युद्ध का क्षेत्र बनाता है तो समूची दुनिया में तेल की बड़ी कमी पैदा होगी और तेल के दाम बढ़ेंगे। इसका सीधा प्रभाव अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी होगा।

मैं कई बार पूर्व में भी लिख चुका हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई प्रभावी भूमिका नहीं बची। इस्लामिक देश भी कई कारणों से बंटे हुए हैं। वैसे तो अमेरिका हमले को रूस, चीन, पाक, सऊदी अरब और ओमान ने अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताकर निंदा की है। परंतु यह निंदा फिलहाल सिया और सुन्नी के मध्य विभाजित है। पाकिस्तान जो अमेरिकी मदद के समर्थन पर जिंदा है। वह वैसे भी अपनी जीर्ण क्षीण अर्थव्यवस्था और आंतरिक जनविद्रोह के चलते कुछ मदद करने की स्थिति में नहीं है। उसने चीन को बन रोड वन बेल्ट के लिये अपना भूभाग उपलब्ध कराया है परंतु चीन का यह स्वप्नदर्शी योजना अभी केवल अमूर्तरूप में है। सऊदी अरब आदि देशों के मुखिया भी स्वतरू युद्ध के लड़ने के पक्ष में नहीं है। चीन की जमीनी दूरी ईरान से इतनी अधिक है कि चीन भी कोई वास्तविक मदद पहुँचाने की स्थिति में नहीं है और यह युद्ध होता है तो रूस व चीन की इसमें भौतिक व वास्तविक भागीदारी नगण्य होगी, चीन की तो बिल्कुल ही प्रतीकात्मक।

जहाँ एक तरफ दुनिया को इन समस्याओं का व्यावहारिक हल खोजना होगा वहीं युद्ध व हथियारों की वास्तविकताओं को भी समझना होगा। एक बड़ी समस्या यह है कि इस समय दुनिया और वैश्विक मीडिया भी एलगोरिदम का शिकार है और यह समस्या निरंतर बढ़ रही है। राजनीति व मीडिया का एक धड़ा इस्लामिक फोबिया से ग्रस्त है और उसके विचार व नीतियाँ भी उसी से प्रभावित है। इसके कारण न केवल मानसिक,विभाजन होता है बल्कि युद्ध के हालात बनते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी इससे प्रभावित हैं और हावर्ड विश्वविद्यालय की शैक्षणिक आजादी खत्म कर अपने वैचारिक पैमाने पर लाने के लिये जिस प्रकार के कदम उन्होंने उठाये हैं वह इसी बात का प्रमाण है। हाल ही में उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी के न्यूयार्क मेयर के प्रत्याशी श्री ममदानी के चयन के बाद उन्होंने जो बयान दिया कि यदि ममदानी नहीं सुधरेंगे तो वे न्यूयार्क म्युनिसपल कारपोरेशन की सरकारी मदद बंद कर देंगे, यह भी इसी का प्रमाण है। ऐसा लगता है कि श्री ट्रंप दो युद्ध लड़ रहे हैं या लड़ने की तैयारी में हैं। एक वैश्विक जमीनी युद्ध और दूसरा अपने विचारों के बंद घेरे का युद्ध। इस दूसरे युद्ध के लिये उन्हें बाहर वालों से कम अपनों से अधिक लड़ना पड़ रहा है। उन्हें अपने देश, अपनी पार्टी और अपने देश की संस्थाओं से लड़ना पड़ रहा है। स्वाभाविक है कि इससे उनके प्रति अमेरिकी मानस में अभी तो विरोध बढ़ रहा है हालाँकि भविष्य में यह क्या स्वरूप लेगा, क्या अमेरिकी मानस ट्रंप के विचारों के साथ खड़ा रहेगा या अपनी वैचारिक स्वतंत्रता जो असीमित रही है, पर ही चलेगा, ये प्रश्न भविष्य के गर्भ में है।

परंतु युद्ध की इन संभावनाओं के चलते हथियारों और युद्ध की तैयारी पर जिस प्रकार खर्च बढ़ रहा है वह समूची दुनिया के विकास के लिये चिंता का विषय होना चाहिये। वर्ष 2024 में समूची दुनिया में 235 लाख करोड़ रुपया देशों के रक्षा बजट में रखा गया था और इस वर्ष प्राप्त सूचनाओं के अनुसार इसमें 20 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है। परमाणु हथियारों पर ही लगभग 9 लाख करोड़ रुपया पिछले वर्ष खर्च हुए थे, अब और अधिक बढ़ेंगे। स्थिति यह है कि जो महाविनाशक हथियार हैं उन पर दुनिया में हर क्षण लगभग 3 लाख करोड़ रुपया खर्च हो रहे हैं। जितनी राशि पिछले वर्ष परमाणु हथियारों पर खर्च हुई है, उतनी राशि से 68 करोड़ लोगों को भोजन मिल सकता था। ऐसी नीतियों को दुनिया कब तक चलायेगी, कब तक सहेगी यह देखना है। क्या इसके विरुद्ध दुनिया खड़ी होगी या फिर दुनिया किसी एक परमाणु शक्तिशाली देश की, उस देश के एक शीर्ष शक्ति वाले व्यक्ति की गुलाम बन जायेगी। वैसे भी दुनिया के लगभग 150 देश आज विदेशी कर्जों के जाल में हैं। गरीब देशों या कर्जदार देशों पर लगभग 94 लाख करोड़ रुपया कर्ज का बकाया है और इसमें सबसे बड़ा साहूकार चीन है। इजराइल व हमास के युद्ध में और रूस व यूक्रेन के युद्ध में जो तबाही के मंजर सामने आये हैं वे कब और कैसे पूरे होंगे कहना कठिन है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी के अनुसार 15 जनवरी 2025 तक अकेले गाजा पटटी में 46710 लोग मारे गये हैं। याने हर पचास में से एक व्यक्ति मारा गया और हर 20 में से एक व्यक्ति घायल हुआ है। गाजा पटटी में ही अकेले 18000 निर्दोष बच्चे मारे गये हैं। रूस व यूक्रेन के युद्ध में भी हजारों मौतें हुई हैं और उसके साथ-साथ यूक्रेन के 69 लाख लोग देश छोड़ने को लाचार हुए। हथियार और युद्ध मानवता को मार रहे हैं। हथियार से, भूख से, विस्थापन से और युद्धजनित बीमारियों से। अमेरिकी समाचार पत्रों में गाजा में हाथों में कटोरे लिये भूखे नागरिकों व बच्चों के चित्र छप रहे हैं और उन्हें देखकर किसी भी इंसान के मन का भावविह्वल होना स्वाभाविक है, दुनिया में लगभग 473 मिलियन बच्चे युद्ध के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। मैं फिर एक बार कहूँगा कि दुनिया के इन मुद्दों और मानवता के सामने खड़े संकटों से बचने के दो ही रास्ते हैं, एक गाँधी और दूसरा डॉ.लोहिया के सपनों की विश्व संसद। देखें दुनिया किसे चुनती है, हथियार और युद्ध या गाँधी और लोहिया?

क्या हम अपने शहर की स्वच्छता के बारे में सोचते हैं?

दृष्टिकोण

भूपेन्द्र भारतीय

लेखक अधिवक्ता हैं।

एक बार फिर इंदौर महानगर आठवीं बार देश में सबसे स्वच्छ नगर रहा। यह इंदौर व मालवा वासियों के लिए बड़े गर्व का विषय है। यह एक कार्य नहीं, संस्कृति बन गया है। स्वच्छता संस्कृति। लेकिन क्या हम जिस नगर, कस्बे व गाँव में रहते है उसकी स्वच्छता के बारे में इंदौर जैसे उदाहरण को देखकर विचार करते है। माना इंदौर व देश के कुछ अन्य नगरों में स्वच्छता के मामले में अच्छा कार्य हो रहा है। स्वच्छता को एक महत्वपूर्ण संस्कृति की तरह लोग इसे अपना रहे हैं। लेकिन भारत में यह डगर अभी बहुत लंबी है। यूरोप व अन्य विकसित देशों की तुलना में अभी भारत स्वच्छता के मामले में बहुत पीछे है। स्वच्छता हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में है और ऐसे में किसी भी समाज व राष्ट्र को प्रगति करना है तो स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना होता है। यदि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है तो उसे स्वच्छता के मामले में निरंतर प्रगति करना होगा।

हम सब अपने नगर में अब भी देखते हैं कि आवारा व जानबूझकर छोड़े गए पशु सड़कों पर बैठे रहते है। ऐसे में हम यब सब लापरवाही नगरपालिका व सरकारी व्यवस्था पर छोड़कर बचते हैं। नागरिक अपने कर्तव्यों से भागते हैं। नागरिक अपनी जान बचाकर प्रतिदिन इन पशुओं के पास से निकलते हैं। लोग अब भी सरकारी भवनों व सार्वजनिक खुले स्थान पर थूकते, पिशाब करते, कचरा फेंकते मिल जाऐंगे। नगर में गंदगी करना जैसे उनका मौलिक अधिकार हो। सड़कों पर

आवारा पशुओं के कारण गंदगी के साथ ट्राफिक एक बड़ी समस्या बन जाती है। कोई नगर कचरे से ही गंदा नहीं होता है, उसके गंदे होने में अतिक्रमण का भी एक बड़ा कारण रहता है। सही जल निकासी नहीं होना, नालियों में कचरा व मिट्टी भरकर अतिक्रमण कर लेना भी हमारे नगर की गंदगी व पीछड़ेपन का एक बड़ा कारण होता है। प्लास्टिक एक बड़ी समस्या है, इसके लिए नागरिकों को प्लास्टिक को छोड़ने की आदत डालना ही होगा। विवाह व अन्य आयोजनों में भोजन बड़ी मात्रा में फेंकना गिले कचरे का कारण बनता है। लंबे समय से हमारी मानसिकता बन गई है कि हमारे घर के आसपास व नगर की स्वच्छता के लिए पूर्णतः नेता व सरकारी व्यवस्था जिम्मेदार है। लेकिन क्या यह हमारी जिम्मेदारी नहीं कि हम समय समय पर इसके लिए आवाज उठाये व हम स्वयं भी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से गंदगी ना करें। क्या हम अपने नगर की नगरपालिका के स्वच्छता कर्मचारियों का ध्यान रखते है? उनसे अच्छा व्यवहार करते हैं। उनके साथ वर्ष में एक बार कोई विशेष आयोजन कर भोजन करते हुए उनके परिवार, स्वास्थ्य, उनके बच्चों की शिक्षा, आर्थिक समस्याओं पर बातचीत करते हैं?

अपने घर के आसपास व नगर की स्वच्छता के लिए हम पीछली बार कब सड़क पर उतरे थे? आखिर हम अपने समाज, गाँव व नगर की स्वच्छता पर कितना समय देते हैं और जिम्मेदार लोगों को कितना कटघरे में खड़ा करते है।

कोई भी अच्छी संस्कृति, सभ्यता व व्यवहार नेताओं व राजनीतिक व्यवस्था से पूरी तरह नहीं बनती है, उसके लिए जनभागीदारी व जनइच्छा की भी आवश्यकता होती है। सरकारी मशीनरी हमारे प्रोत्साहन व सहयोग के लिए है यदि हम जागरूक होकर उसका उपयोग करते है तो। नहीं तो वह सरकारी मशीनरी कागजों में ही सिमट कर रह जाती है व नागरिकों का शोषण करने लगती हैं। पीछले दस वर्षों में भारत में स्वच्छता की यह जो संस्कृति व क्रांति आई है इसे हमें अपने गाँव-गाँव व राष्ट्र के प्रत्येक नगर के नागरिकों को स्वेच्छा से अपनाना चाहिए व एक जागरूक नागरिक की तरह इस स्वच्छता संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करना चाहिए। इस स्वच्छता संस्कृति को स्वेच्छा से अपनाने में जो समय लगना था वह लग चुका है। अब हमें इसे नियम की तरह ही मानना भी होगा।

इच्छाओं की अंतहीन यात्रा

अभिव्यक्ति

अदिति सिंह भदौरिया

लेखक स्तंभकार हैं।

मनुष्य का संपूर्ण जीवन एक यात्रा है,बाहरी भी और भीतरी भी। परंतु यदि इस यात्रा का सबसे प्रभावी और सशक्त चालक तत्व कोई है, तो वह है इच्छा। यही इच्छा उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, लक्ष्य निर्धारित कराती है, और संघर्षों से टकराने का साहस भी प्रदान करती है। परंतु जब यही इच्छाएँ सीमाओं का अतिक्रमण कर लेती हैं, तो यह यात्रा इच्छाओं की अंतहीन यात्रा बन जाती है। एक ऐसी दौड़, जिसका कोई ठिकाना नहीं, कोई विराम नहीं।

प्राचीन भारतीय दर्शन में 'काम' को पुरुषार्थ चतुष्टय में एक आवश्यक अंग माना गया है। यह इस बात का द्योतक है कि इच्छा का होना कोई दोष नहीं, बल्कि यह जीवन की सहज और स्वाभाविक प्रवृत्ति है। भोजन की इच्छा, सुरक्षा की आवश्यकता, स्नेह की चाह,यह सब हमारे अस्तित्व के मूल में स्थित हैं। इन्हीं के माध्यम से हम ज्ञान, प्रेम और आत्म-उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं।

किन्तु समस्या तब उत्पन्न होती है जब यह इच्छाएँ अपनी स्वाभाविक सीमाओं को पार कर असीमित आकांक्षाओं का रूप ले लेती हैं। तब जीवन की दिशा स्पष्ट न रहकर केवल एक अनवरत दौड़ बन जाती है। एक ऐसी अंतहीन यात्रा, जहाँ मंज़िल सदैव कुछ कदम आगे दिखाई देती है, परंतु कभी पहुँच में नहीं आती।

मानव मन की प्रकृति ही ऐसी है कि वह उपलब्धि के बाद संतुष्टि नहीं, इसका कारण है तुलना और प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति। जब मनुष्य अपने चारों ओर दूसरों की उपलब्धियों को देखता है, तो वह स्वयं की स्थिति से असंतुष्ट हो जाता है। यह असंतोष ही इच्छाओं को निरंतर हवा देता है और उन्हें अनंत की ओर ले जाता है।

आधुनिक युग में तकनीकी विकास ने मनुष्य की जीवन-शैली को जितना सुगम बनाया है, उतना ही उसकी इच्छाओं को जटिल और अगम्य भी बना दिया है। आज का उपभोक्तावादी समाज निरंतर यह संदेश देता है कि आपके पास जो है, वह पर्याप्त नहीं है। फलस्वरूप, मनुष्य का मन हर क्षण नवीनतम वस्तु, अनुभव या पहचान की ओर आकर्षित होता है। ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म, सोशल मीडिया, और विज्ञापनों की दुनिया में एक अदृश्य दौड़ चल रही है। जिसमें भाग लेते हुए हम भूल जाते हैं कि वास्तविक संतोष कहीं बाहर नहीं, भीतर से आता है। इसका अर्थ यह नहीं कि इच्छाएँ बुरी हैं, अपितु यह कि अनियंत्रित और अंधाधुंध इच्छाएँ आत्मा के वास्तविक स्वरूप को ढक देती हैं और व्यक्ति को अपने ही भ्रमजाल में उलझा देती हैं।

इस अंतहीन यात्रा का समाधान इच्छाओं का दमन नहीं, बल्कि संतुलन और विवेक है। मनुष्य को यह सीखना होगा कि किस इच्छा का पीछा करना सार्थक है और किसे छोड़ देना चाहिए। आत्मनिरीक्षण, ध्यान, साधना और नैतिक शिक्षा के माध्यम से हम अपने भीतर एक ऐसा बुद्धिमत्ता का दीप जला सकते हैं, जो हमें अंधी दौड़ से निकाल कर सार्थक जीवन की ओर ले जाए। इच्छाओं को साध्य नहीं, साधन बनाना होगा। यदि कोई इच्छा हमें बेहतर मनुष्य बनने, समाज के प्रति उत्तरदायी बनने, या आत्मविकास करने की प्रेरणा देती है तो वह निश्चय ही सकारात्मक है। परंतु यदि वह केवल भोग, वर्चस्व और दिखावे के लिए है, तो वह अंततः दुखदायी सिद्ध होती है।

इच्छाओं की अंतहीन यात्रा एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई भी मानव पूर्णतः अछूता नहीं है। यह यात्रा मानव विकास का भी प्रतीक है और पतन का भी कारण बन सकती है। यह इस पर निर्भर करता है कि हम अपनी इच्छाओं को कहाँ तक ले जाते हैं। क्या हम उनके स्वामी बनते हैं या वे हमारी लगाम थाम लेती हैं।जीवन को सार्थक और शांतिपूर्ण बनाने के लिए आवश्यक है कि हम इच्छाओं को अपने भीतर पहचानें, उन्हें विवेकपूर्ण दिशा दें, और यह स्वीकारें कि हर इच्छा की पूर्ति आवश्यक नहीं होती। कभी-कभी त्याग में, संयम में, और संतोष में भी एक गहरी पूर्णता छिपी होतीहै।

सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं 662, साई कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
स्थानीय संपादक
हेमंत पाल
प्रबंध संपादक
रमेश रंजन त्रिपाठी

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,
Mobile No.: 09893032101
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

संजय तेलंग

(वरिष्ठ पत्रकार एवं व्यंग्यकार)

इंदौर का नाम जामनगर क्यों न कर दिया जाए

देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में इंदौर ने सात बार जरूर नाम कमाया, लेकिन शहर के अनियंत्रित ट्रैफिक की कुख्याति भी देशभर में है। इंदौर की सड़कों पर दिनभर में कई बार जाम लगना सामान्य बात है। ध्वस्त हो चुकी शहर की ट्रैफिक व्यवस्था ने इंदौर वालों का जीना मुहाल कर रखा है। रोज-रोज की इस परेशानी से आजिज आ चुके इंदौर वासियों ने अब शहर का नाम ही बदल डालने का मन बना लिया है। उनकी सोच है कि बार-बार ट्रैफिक जाम जिस शहर की पहचान बन चुकी है, उसे क्यों न 'जामनगर' नाम दे दिया जाए। इस नाम को लोकप्रियता मिलते देर भी नहीं लगेगी। नाम लेते ही पता चल जाएगा शहर की नस-नस का हाल!

नाम बदलने का लाभ इंदौर वालों को भले ही न हो, लेकिन बाहर से आने वाले वाहन चालकों को मिलने की गारंटी है। शहर की सीमा में प्रवेश करने से पहले ही उन्हें मालूम होगा कि अब वे ट्रैफिक जाम नगर में प्रवेश करने जा रहे हैं। साथ में दाना-पानी जुटा लेंगे, तो जाम में फंसने पर भी कम से कम भूखे तो नहीं मरेंगे। ऐसा नहीं है कि इंदौर वालों को नाम बदलने का बिल्कुल ही लाभ नहीं होगा, स्वच्छता की स्नातक डिग्री मिलने के बाद शहर को स्नातकोत्तर डिग्री मिलने का जश्न भी वे मना सकते हैं। सफाई में नाम कमाने के साथ ट्रैफिक जाम के मामले में भी हम गर्व से कह सकेंगे कि हम सबसे आगे हैं और देश में अग्रणी हैं।

वैसे जामनगर नाम का शहर गुजरात में है। तो क्या हुआ, क्या एक नाम के दो शहर नहीं हो सकते! एक नाम के दो शहर या गांवों की हमारे देश में कमी नहीं है। एक ढूंढने जाएंगे तो दस मिल जाएंगे। सौ की सच्ची बात तो यह कि गुजरात के जामनगर का नाम बदल कर जामुन नगर कर दिया जाए। इस रसीले नाम पर किसी को आपत्ति भी नहीं हो सकती, पौष्टिक फल का नाम है। जामनगर (गुजरात) वाले भी खुश हो जाएंगे कि अब उनका शहर जाम के बदनाम नाम से नहीं पहचाना जाएगा। एक बात और, हमारे देश में शहरों और गांवों के नाम बदलने का सिलसिला तो चल ही रहा है। ऐसे में क्यों न बहती गंगा में हाथ धो लिए जाएं।

ऐसा भी नहीं है कि शहर का ट्रैफिक सुधारने के प्रयास नहीं हुए या नहीं हो रहे। शहर के पटेल प्रतिमा चौराहे पर तो इतने प्रयोग हो चुके हैं कि प्रयोग करने वालों की सांसें फूलने लगी हैं। लेकिन कमबख्त बिगड़ा ट्रैफिक है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। साढ़े तीन सौ करोड़ में बने बीआरटीएस को शहर के सुगम ट्रैफिक में बाधा मान कर उखाड़ने की तैयारी है। छुट्टी के दिन समाज सेवी संस्थाएं, स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थी और कुछ बुजुर्ग व महिलाएं भी कभी चौराहों पर ट्रैफिक संभालते दिख जाएं तो अचरज बिलकुल न कीजिएगा।

ये लोग वाहन चालकों को समझाइश देते हैं। नियमों का पालन करने पर फूल भेंट करते हैं। इस दौरान इनकी गतिविधियां कैमरों में कैद होती रहती हैं। मजेदार बात यह है कि जिनके काम में ये सहयोग कर रहे होते हैं, वे दूर किसी कोने में मोबाइल में व्यस्त हो जाते हैं। एक दिन की इस मशक्कत का परिणाम अगले दिन अखबारों में फोटो और खबर प्रकाशन। अरे जिस ट्रैफिक को यातायात के कठोर नियम और बड़े-बड़े अधिकारी सैकड़ों बैठकों में सालों में ठीक नहीं कर पाए, उसे एक दिन में कौन ठीक कर पाएगा! हां, यह भी जान लें कि इंदौर जामनगर बनते ही ट्रैफिक जाम का संकेत तो देगा ही, साथ इसमें छिपे एक और गहरे अर्थ का संकेत भी अपने आप संबंधितों तक पहुंच जाएगा। बात शाम ढलते ही छलकने वाले 'जाम' की है। इस जाम के दीवानों की इंदौर में कमी नहीं है। शाम ढले ठेकों और ठेकों के पास (बंद होने के बाद भी संचालित) अहातों में जुटने वाली बेतहाशा भीड़ को देख कर सहज ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है।

शहर में दिनों-दिन बढ़ती पब्स और बार की संख्या भी यह बताने के लिए पर्याप्त है कि हम इस मामले में भी किसी से कम नहीं हैं! अब सही-सही आंकड़ा तो बताना मुश्किल है, लेकिन हर दिन लाखों की तो पी ही जाते होंगे यहां के बंदे। यकीन मानिए, इंदौर का नाम जामनगर होते ही बधाइयों की बौछार होते देर नहीं लगेगी। लोग तारीफों के पुल बांधेंगे, शहर को देशभर के अखबारों में सुर्खियां मिलेगी और क्या चाहिए! अरे जाम का क्या है, जाम लगता रहेगा और अपनी मर्जी से खुलता भी रहेगा। हम और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते।

कानून और न्याय

विनय झैलावत

(पूर्व असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता)

अवैध निर्माण एवं तोड़फोड़ पर सख्ती जरूरी

अवैध निर्माणों पर सर्वोच्च न्यायालय ने कठोर कदम उठाने के आदेश दिए हैं। उस क्षेत्र की सभी संपत्तियों को सील करने का निर्देश दिया, जहां अनाधिकृत या अवैध निर्माण होता पाया जाता है। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने बुलडोजर से तोड़फोड़ की कार्रवाई पर भी रोक के आदेश दिए। दिल्ली के चांदनी चौक में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध और अनाधिकृत निर्माण की निंदा भी की। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को गिरफ्तार करें जो इस क्षेत्र में एक भी अनाधिकृत ईंट लगाते हुए पाया जाए।

सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के चांदनी चौक में कथित अवैध और अनाधिकृत व्यावसायिक निर्माण और दिल्ली नगर निगम द्वारा इससे निपटने में विफलता की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने की इच्छा व्यक्त की थी। इसके बाद न्यायालय ने क्षेत्र में आवासीय भवनों को व्यावसायिक परिसरों में बदलने पर रोक लगा दी गई। न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम को भी आगाह किया कि ऐसे मामलों में किसी भी तरह की अवमानना न केवल न्यायालय की अवमानना मानी जाएगी, बल्कि नगर निगम अधिकारियों और संबंधित बिल्डरों के बीच मिलीभगत के बारे में प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने का भी आधार बनेगी।

सुनवाई की शुरुआत में न्यायालय ने कहा कि आखिरकार दिल्ली नगर निगम अपनी नींद से जाग गया है और कुछ कदम उठा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाला बागची की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और उस क्षेत्र की सभी संपत्तियों को सील करने का निर्देश दिया, जहां अनाधिकृत या अवैध निर्माण होता पाया जाता है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने दिल्ली पुलिस अधिकारियों से यह भी कहा कि "आप रोज गश्त के लिए जाते हैं। अगर कोई ईंट लगाते पाया जाता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। यह नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा एक बड़ा धोखा है। इसे रोका जाना चाहिए।

आदेश में कहा गया कि पुलिस आयुक्त क्षेत्र में गश्त के लिए पुलिस दल तैनात करेंगे। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली नगर निगम द्वारा पारित सभी ध्वस्तीकरण नोटिस, जिन पर अदालतों ने स्थगन नहीं दिया है, उनका सावधानीपूर्वक पालन किया जाए। जहां अवैध/अनाधिकृत निर्माण हो रहे हैं, ऐसी संपत्तियों को तुरंत सील कर दिया जाए। स्थानीय पुलिस उपायुक्त द्वारा एक अनुपालन रिपोर्ट भी दाखिल की जाए। न्यायालय ने उस संपत्ति का भी संज्ञान लिया, जिसके भूतल पर एक वृद्ध महिला रहती है। इसमें नगर निगम के अधिकारियों से वह महिला एक बिल्डर द्वारा उसकी आवासीय संपत्ति पर व्यावसायिक मंजिल के अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगा रही है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने दिल्ली नगर निगम से पूछा कि सन् 2022 में यह बिल्डर काम शुरू कर रहा है। यह वृद्ध महिला भूतल पर रहने वाली अधिकारियों के सामने रो रही है। दर-दर भटक रही है। आप कुछ नहीं करते। जब हम आदेश देते हैं, तो आप जाकर सब कुछ तोड़ देते हैं। आप इतने सालों से क्या रह थे? अपने आदेश में न्यायालय ने बिल्डर का विवरण मांगा, ताकि उसके खिलाफ उचित दंडात्मक कार्रवाई की जा सके। अंतत: खंडपीठ ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसडी संजय से कहा कि वे दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करवाएं। क्योंकि, वे अपने तौर-तरीके नहीं बदलेंगे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने टिप्पणी कि देखते हैं उन्हें कौन जमानत देता है।

हालांकि, इसने इस बात की जांच की कि निगम ने कुछ घरों के संबंध में क्या किया था, जिन्हें गुप्त तरीके से एक साथ मिला दिया गया था। घरों से संबंधित एक आवेदन पर दिल्ली नगर निगम से जवाब तलब करते हुए न्यायालय ने आदेश दिया कि किसी भी व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि आवश्यक हो तो संपत्तियों को सील किया जा सकता है। न्यायालय ने मौखिक रूप से दिल्ली नगर निगम को निरीक्षण रिपोर्ट दाखिल करने और याचिकाकर्ता को अनधिकृत निर्माण के किसी भी अन्य मामले को हलफनामे के साथ रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने मामले को समाप्त करने से पहले यह भी कहा कि हमारे आदेशों के बावजूद, ये लोग कितने दुस्साहस दिखा रहे हैं। लेकिन, उच्चतम न्यायालय ने केवल अवैध निर्माण नहीं बल्कि अवैध तोड़फोड़ पर भी कड़ा रूख अपनाया। एक अन्य प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने बुलडोजर एक्शन पर भी सख्त रूख अपनाया है। उत्तर प्रदेश में एक मकान को ध्वस्त करने से संबंधित तमामले में सर्वोच्च न्यायालय ने शनिवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि बुलडोजर जस्टिस की कोई जगह नहीं है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि कानून के शासन में बुलडोजर न्याय की कोई जगह नहीं है। उनका कहना था कि अगर इसकी अनुमति दी गई, तो अनुच्छेद 300ए के तहत संपत्ति के अधिकारों की संवैधानिक मान्यता खत्म हो जाएगी। न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को मुआवजे के रूप में पीड़ित व्यक्ति को 25 लाख रूपये देने का निर्देश भी दिए। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के रहने वाले मनोज टिबड़ेवाल आकाश का घर साल 2019 में सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत ध्वस्त कर दिया गया था। मनोज टिबड़ेवाल आकाश के इस घर पर बुलडोजर चलाया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय कहा था कि नागरिकों की संपत्तियों को नष्ट करने की धमकी देकर उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। न्यायालय ने कहा कि बुलडोजर न्याय न केवल कानून के शासन के खिलाफ है बल्कि यह मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। अपने फैसले में न्यायालय ने कहा कि लोगों की संपत्तियों और उनके घरों को तोड़कर उनकी आवाज को नहीं दबाया जा सकता है। एक व्यक्ति के पास जो सबसे बड़ी सुरक्षा होती है, वह उसका घर ही है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार को किसी भी व्यक्ति की संपत्ति ध्वस्त करने से पहले कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए और उन्हें सुनवाई का मौका देना चाहिए। न्यायालय का कहना था कि अगर किसी विभाग या अधिकारी को मनमाने और गैरकानूनी व्यवहार की इजाजत दी जाती है तो इस बात का खतरा है कि प्रतिशोध में लोगों की संपत्तियों को ध्वस्त किया जा सकता है। अवैध तरीके से मकान तोड़ने वालों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को कार्यवाही के निर्देश किए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा करने वाले सरकारी अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने को कहा है।

सर्वोच्च न्यायालय का कहना था कि न सिर्फ इस मामले में बल्कि इस तरह के अन्य मामलों में भी अगर कोई अधिकारी शामिल पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। इस मामले में न्यायालय ने मुख्य सचिव से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के आदेश के तहत एफआईआर दर्ज करवाने के लिए भी कहा है। इसकी जांच सीबी-सीआईडी करेगी। सीबी-सीआईडी का नेतृत्व पुलिस महानिदेषक स्तर के आईपीएस अधिकारी करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि राज्य सरकार को सड़क चौड़ीकरण परियोजना लागू करने से पहले कुछ खास बातों का पालन करना चाहिए। आधिकारिक रिकॉर्ड और मैप के मुताबिक सड़क की मौजूदा चौड़ाई का पता लगाना चाहिए। साथ ही चौड़ीकरण के समय सर्वे करना चाहिए और पुराने रिकॉर्डस को देखकर यह पता लगाना चाहिए कि कितना अवैध अतिक्रमण हुआ है। अगर अवैध अतिक्रमण पाया जाता है तो ऐसा करने वाले को उचित तरीके से लिखित नोटिस जारी कर, अतिक्रमण हटाने के लिए कहा जाना चाहिए। अगर सड़क चौड़ीकरण के समय राज्य सरकार को भूमि की जरूरत है तो कानून के मुताबिक भूमि का अधिग्रहण किया जाना चाहिए।

विश्व राजनीति

डॉ. सुधीर सक्सेना

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

'द्रुजों' की आड़ में क्या गुल खिलायेगा सीरिया पर इजरायली धावा?

यह पहला मौका नहीं है, जब इजरायली विमानों ने दमिश्क पर बम बरसाये हैं। इजरायल के बम वर्षकों ने गत वर्ष मई में राजधानी में बम गिराये थे, लेकिन 15 और 16 जुलाई को उसकी बमबारी कहीं अधिक सटीक और घातक थी। 15 जुलाई को इजरायली विमानों ने तटीय सुवैदा प्रांत में सीरिया के सैनिक बलों और वाहनों का निशाना बनाया और 16 जुलाई को अपने दुस्साहसिक अभियान में उसने सीरिया के रक्षा मंत्रालय और फौजी मुख्यालय पर बमबारी कर उन्हें तबाह कर दिया। इजरायल ने यही बस नहीं किया, बल्कि हमले और होंगे का ऐलान कर सीरिया की तकरीबन एक छमाही पहले सत्ता में आई इस्लामी हुकूमत को सांसत में डाल दिया। सीरिया के लिये यह धावा और ज्यादा मुसीबतजदा इस नाते है कि वह बीते करीब एक दशक से गृह युद्ध की विभीषिका में झुलस रहा है।

ईरान और इजरायल में जंग थम गयी है, लेकिन अशांत और तनावग्रस्त युद्ध जर्जर मध्यपूर्व में 16 जुलाई को सीरिया की राजधानी दमिश्क पर इजरायली धावे के साथ ही युद्ध का एक नया मोर्चा खुल गया है। इजरायल के रक्षा मंत्री यिस्राइल काट्ज ने मंगलवार को दमिश्क में इजरायल की बमबारी को महज चेतावनी निरूपित करते हुए कहा कि अब सीरिया पर दर्दनाक हमलों का दौर शुरू होगा। काट्ज के कथन से स्पष्ट है कि सीरिया अब इस्रायल के आक्रमण की ज़द में है।

यह पहला मौका नहीं है, जब इजरायली विमानों ने दमिश्क पर बम बरसायें हैं। इजरायल के बम वर्षकों ने गत वर्ष मई में राजधानी में बम गिराये थे, लेकिन 15 और 16 जुलाई को उसकी बमबारी कहीं अधिक सटीक और घातक थी। 15 जुलाई को इजरायली विमानों ने तटीय सुवैदा प्रांत में सीरिया के सैनिक बलों और वाहनों का निशाना बनाया और 16 जुलाई को अपने दुस्साहसिक अभियान में उसने सीरिया के रक्षा मंत्रालय और फौजी मुख्यालय पर बमबारी कर उन्हें तबाह कर दिया। इजरायल ने यहीं बस नहीं किया, बल्कि हमले और होंगे का ऐलान कर सीरिया की तकरीबन एक छमाही पहले सत्ता में आई इस्लामी हुकूमत को सांसत में डाल दिया। सीरिया के लिये यह धावा और ज्यादा मुसीबतजदा इस नाते है कि वह बीते करीब एक दशक से गृह युद्ध की विभीषिका में झुलस रहा है। गत वर्ष दिसंबर में उसे असद के लंबे शासन से बमुश्किल मुक्ति मिली और पूर्व जेहादी अहमद-अल-शारा के नेतृत्व में इस्लामी हुकूमत अस्तित्व में आई। फिलवक्त शारा की फौजू समूचे सीरिया में अपना प्रमुख और नियंत्रण स्थापित करने के फेर में है और उन्हें कुछ भागों में प्रतिरोध और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहां यह उल्लेखनीय है कि असद को रूस का खुला समर्थन और सहायता प्राप्त थी और उसी के बूते वह करीब एक दहाई अपनी सत्ता बनाये रखने में कामयाब रहे। सीरिया में संकट का एक बड़ा सबब अल्पसंख्यक समुदाय भी हैं। देश में अमन-चैन के मकसद से ही अहमद-अल-शारा ने सत्ता में आने के बाद अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की कसम खाई, लेकिन इससे बात बनती नज़र नहीं आई। देश के दक्षिणी सूबे में सुवैदा में जहां द्रुज मिलीशिया और सरकारी सैनिकों में झड़पे लगातार जारी हैं, वहीं इजरायल ने ताजा बमबारी की वजह भी द्रुजों को सुरक्षा मुहैया करना बताया है।

कौन हैं ये द्रुज? करीब पांच वर्ष पूर्व अपने इजरायल प्रवास के दरम्यान मैंने अपनी मेजबान डच मूल की यहूदी रूथ डी जोंग के जरिये द्रुजों के बारे में जाना। उनके दूरस्थ पहाड़ी कस्बे में कुछ द्रुज परिवार भी रहते थे। द्रुज वस्तुत: मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय है, जो अपनी विशिष्ट धार्मिक परम्पराओं का पालन करता है। द्रुज इजरायल, सीरिया और लेबनान में बसे हुये हैं। इस्रायल में यहूदी शासन से इनके रिश्ते सौहार्द्रपूर्ण हैं और अनेक द्रुज इजरायली फौज में शरीक हैं। दस लाख से अधिक की कुल द्रुज आबादी के आधे सीरिया में रहते हैं तो लगभग 20 फीसद इजरायल और उसके आधिपत्य की गोलन हाइटस में। सीरिया की कुल आबादी की तीन फीसद आबादी द्रुजों की है और वहां की 14 वर्षीय घरेलू उथल-पुथल में द्रुजों ने खुद को हथियारबंद किया है। और अब वे सीरियाई फौजों की पैठ और नियंत्रण का सशस्त्र विरोध कर रहे हैं। उनके इसी प्रतिरोध के चलते अहमद-अल-शारा को वहां प्रभुत्व स्थापित करने में कठिनाई का सामाना करना पड़ रहा है। सूत्रों के अनुसार पिछले दिनों सीरिया की फौजी कार्रवाई में सुवैदा में 350 से अधिक लोग मारे गये हैं।

गत वर्ष अप्रैल-मई में फौज और द्रुजों में पहलेपहल हिंसा भड़कने के पहले फौजों और अल्वियों में संघर्ष भड़का था और सैकड़ों मारे गये थे। गौरतलब है कि अपदस्थ राष्ट्रपति बशर-अल-असद अल्वी समुदाय से ताल्लुक रखते थे।

बहरहाल, इस्रायल ने इन्हीं द्रूजों को सुरक्षा के नाम पर सीरिया पर धावा बोला है। तेल अवीव इस अभियान से अरब राष्ट्र के अल्पसंख्यक समूहों से रिश्ते गांठन/चाहता है। दूसरे वह अपनी सीमाओं की चौतरफा सुरक्षा चाहता है। दिसंबर में सीरिया के दर्जनों ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमलों के बाद उसने संयुक्त राष्ट्र संघ के गश्ती दलों को धतां बताकर गोलन हाइटस की 'बफर जोन' पर भी कब्जा जमा लिया। अब वह उस सारे इलाके को विसैन्यीकृत करना चाहता है, जहां उसके खिलाफ सैनिक अड्डे पनप सकते हैं। अकेले गोलन पहाड़ियों में ही करीब 25 हजार द्रुज रहते हैं। तेल अवीव चाहता है कि दमिश्क सुवैदा से अपने फौजी वापस बुला ले, ताकि द्रुज चैन से रह सकें। इसके विपरीत शारा-हुकूमत द्रुजों के नि:शस्त्रीकरण की हिमायती है। इसमें शक नहीं कि इजरायल को अमेरिका की शह प्राप्त है। सुवैदा में द्रुजों का हिकमत अल हिजरी संगठन हथियारबंद संघर्ष का पक्षधर है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दफ्तर से मंगलवार को जारी विज्ञप्ति में द्रुज बिरादरी की हिफाजत के प्रति वचनबद्धता की बात दोहरायी गयी है। उत्तरी इजरायल में कार्मेल और गैलिली के द्रुज युवक सन् 67 से इजरायली फौज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अरब देशों ने इजरायली कार्रवाई की निंदा जरूर की है, किंतु आसार हैं कि द्रुजों की रक्षा के बहाने इजरायल अपनी सीमाओं को निरापद करने की मुहिम के तहत सीरिया के खिलाफ आक्रामक सैनिक कार्रवाई जारी रखेगा।

साहित्य

विवेक रंजन श्रीवास्तव

लेखक व्यंग्यकार हैं।

समय के साथ बदलता व्यंग्य का स्वर

व्यंग्य लेखन में यह परिवर्तन केवल शैली का नहीं, मूल्य का भी है। पहले व्यंग्य का आधार मूल्यों की रक्षा था। नैतिकता, ईमानदारी, सादगी, सहिष्णुता जैसे मूल्यों की गिरावट पर प्रतिक्रिया व्यंग्य बन रही है। आज का व्यंग्य कभी कभी उन मूल्यों को ही संदिग्ध ठहराता है। वह पूछता है कि नैतिकता किसके लिए? ईमानदारी क्यों? अब व्यंग्य केवल व्यवस्था पर नहीं, मूल्य व्यवस्था पर भी प्रहार करता है। यह बदलाव एक ओर व्यंग्य को और भी गहरा बना सकता है, तो दूसरी ओर उसे विखंडन का शिकार भी कर सकता है।

व्यंग्य भारतीय साहित्य की वह धारा है, जो समय की करवट के साथ निरंतर रूप और रंग बदलती रही है। यह कोई संयोग नहीं कि व्यंग्य की परंपरा कबीर जैसे संत कवियों से मुखर होती है, जिन्होंने समाज की विसंगतियों, धार्मिक पाखंड और आडंबर पर अपने चुटीले, सीधे लेकिन तीखे शब्दों से वार किया। कबीर का व्यंग्य लोक का व्यंग्य था । जहाँ 'पोथी पढ़-पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय' जैसे दोहे आज भी धार्मिक बाह्याडंबर पर करारा तमाचा हैं। यह व्यंग्य आत्मशुद्धि का साधन था, समाज को आईना दिखाने का एक मार्मिक और साहसी प्रयास बना।

कबीर का व्यंग्य जहाँ आत्मानुभूति और संत परंपरा से उपजा था, वहीं आधुनिक व्यंग्य ने धीरे धीरे अपने स्वरूप में राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना के नए आयाम जोड़े। इस विकासक्रम में हरिशंकर परसाई का योगदान मौलिक और मील का पत्थर है। परसाई ने व्यंग्य को एक सजग नागरिक की भाषा दी ।

सत्ता, प्रशासन, नैतिक पतन और मध्यमवर्गीय ढोंग पर उन्होंने जिस गंभीर हास्य मिश्रण के साथ व्यंग्य का प्रयोग किया, वह व्यंग्य लेखन को महज़ हास्य नहीं रहने देता। उन्होंने व्यंग्य को साहित्य के प्रतिरोधात्मक सामाजिक हस्तक्षेप में बदल दिया। उनकी रचनाएँ 'ठिठुरता हुआ गणतंत्र', 'विकास के बदले घोटाले' या 'राजनीति का अपराधीकरण' जैसे विषयों को लेकर लिखी गई व्यंग्यात्मक टिप्पणियाँ आज भी प्रासंगिक हैं।

काका हाथरसी का व्यंग्य एक अलग दिशा में गया। उन्होंने हास्य को काव्यात्मक जामा पहनाया और चुटीली पद्यात्मक शैली में सामाजिक बुराइयों, नेताओं की दोहरी जुबान और मानवीय मूर्खताओं पर ऐसा प्रहार किया, जो आम जन तक तुरंत पहुँच सके। काका का व्यंग्य मंच का व्यंग्य था । यह तुरंत प्रतिक्रिया देने वाला, हँसी में गूंजने वाला, पर श्रोताओं में गहरे समय तक असर करने वाला परिवर्तन बना जो आज भी कवि मंचों में जीवंत है।

समय के साथ न केवल व्यंग्यकार बदले, व्यंग्य की ज़मीन भी बदली। इक्कीसवीं सदी के व्यंग्यकार अब ऐसे समाज में लिख रहे हैं, जहाँ मीडिया का अतिरेक है, सूचनाओं का विस्फोट है और संवेदनाओं की कमी हो चली है। अब व्यंग्य को हँसाने के लिए नहीं, झकझोरने के लिए लिखा जा रहा है। आज का व्यंग्य सोशल मीडिया के ट्रोल और मीम्स के शोर में भी अपनी जगह बनाता है। परंपरागत व्यंग्य लेखकों की तरह उसे अख़बार या पत्रिकाओं का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, वह डिजिटल दुनिया में फ़ौरन प्रतिक्रिया देता है, पर टिकता कम है। यही वजह है कि आज के व्यंग्य में स्थायित्व की कमी दिखती है । जैसे तात्कालिक लतीफे हों, जो समय के साथ पुराने हो जाते हैं।

विषयों की दृष्टि से भी आज का व्यंग्य अधिक व्यक्तिगत, अधिक राजनीतिक और अधिक वैश्विक हुआ है। जहाँ पहले व्यंग्य का मुख्य उद्देश्य सामाजिक बुराइयों पर कटाक्ष करना था, आज वह व्यक्ति के अस्तित्व, उसकी पहचान, उसकी असुरक्षाओं पर भी सवाल उठाता है। अब व्यंग्य 'मैं' की भाषा बोलता है । वह कभी खुद लेखक की विडंबनाओं से उपजता है, कभी पाठक की उलझनों को स्वर देता है।

शैली में भी व्यापक परिवर्तन आया है। परसाई या शरद जोशी की तरह लंबे व्यंग्य निबंधों की जगह अब छोटी छोटी व्यंग्यात्मक टिप्पणियाँ, व्यंग्य कविताएँ, हास्य चित्र, व्यंग्यीय संवाद या मंचीय प्रहसन अधिक लोकप्रिय हैं। यह परिवर्तन पाठक की बदलती रुचि और जीवन की तेज़ रफ़्तार को दर्शाता है। अब व्यंग्य के पास पाठक का ध्यान खींचने के लिए अधिक समय नहीं होता, उसे दो-तीन पंक्तियों में ही चौंकाना पड़ता है। सम्पादकीय कालम के बाजू में एक नियत स्थान, नियत शब्दों में व्यंग्य ने स्तंभ के स्वरूप में स्थान बना लिया है। समकालीन व्यंग्यकार अपने ऐसे व्यंग्य को किंचित दीर्घायु बनाने के लिए पुस्तक का स्वरूप दे रहे हैं।

व्यंग्य लेखन में यह परिवर्तन केवल शैली का नहीं, मूल्य का भी है। पहले व्यंग्य का आधार मूल्यों की रक्षा था । नैतिकता, ईमानदारी, सादगी, सहिष्णुता जैसे मूल्यों की गिरावट पर प्रतिक्रिया व्यंग्य बन रही है। आज का व्यंग्य कभी कभी उन मूल्यों को ही संदिग्ध ठहराता है । वह पूछता है कि नैतिकता किसके लिए? ईमानदारी क्यों? अब व्यंग्य केवल व्यवस्था पर नहीं, मूल्य व्यवस्था पर भी प्रहार करता है। यह बदलाव एक ओर व्यंग्य को और भी गहरा बना सकता है, तो दूसरी ओर उसे विखंडन का शिकार भी कर सकता है।

कहना न होगा कि व्यंग्य की यह यात्रा कबीर के 'ढाई आखर प्रेम' से लेकर आज के 'फॉरवर्ड मैसेज व्यंग्य' और ट्विटर पर क्रिक रिएक्शन तक अपने समय की सामाजिक और बौद्धिक चेतना का प्रतिबिंब है। लेकिन यह भी सत्य है कि व्यंग्य तब तक प्रभावशाली रहता है, जब तक वह किसी गूढ़ संवेदना से जुड़ा हो। केवल तंज या चुटकुला व्यंग्य नहीं बन सकता। व्यंग्य तब ही सार्थक होता है, जब वह पाठक को हँसाकर सोचने पर मजबूर कर दे, या सोचते हुए हँसा दे।

आज आवश्यकता इस बात की है कि व्यंग्यकार अपनी भाषा में कबीर की बेबाकी, परसाई की विवेकशीलता और काका की चुटीली सरलता को फिर से पिरोएँ। व्यंग्य न केवल समाज का दर्पण है, वह उसकी अंतरात्मा की आवाज़ भी है ।व्यंग्यकार का मौन रोष, उसका विवेकपूर्ण प्रतिरोध यह स्वर साहित्य के दृष्टिकोण से कमजोर नहीं पड़ना चाहिए।

व्यंग्य बदलता रहेगा । विषयों के साथ, माध्यमों के साथ, अभिव्यक्ति के साथ। पर जो नहीं बदलना चाहिए, वह है उसकी संवेदना, उसकी नैतिक दृष्टि और उसका व्यापक जनहित वाला भाव। अगर व्यंग्य अपना मूल यही भाव बनाए रखे, तो वह चाहे मोबाइल स्क्रीन पर हो या मंच पर, किताब में हो या कार्टून में , वह हमेशा प्रासंगिक रहेगा, प्रभावशाली रहेगा, और सबसे बढ़कर, जरूरी बना रहेगा।

ट्रेन से गिरी बेंगलुरु की नर्सिंग छात्रा, मौत

बचाने वाले के सिर में चोट, ट्रेन में चढ़ते समय फिसला हाथ

बैतूल। बैतूल में ट्रेन से गिरने से एक नर्सिंग छात्रा की मौत हो गई। उसे बचा रहा एक व्यक्ति भी नीचे गिर गया, जिससे उसके सिर में चोट आई हैं। घटना की वजह से करीब आधा घंटे तक प्लेटफार्म पर ही ट्रेन रूकी रही। लडक़ी बेंगलुरु में सेकंड ईयर की छात्रा थी और सहेली के साथ जयपुर जा रही थी। हादसा मैसूर से जयपुर जा रही जयपुर एक्सप्रेस (12975) में हुआ। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी थी और छात्रा पानी की बोतल लेने के लिए ट्रेन से नीचे उतरी थी। इसी दौरान ट्रेन अचानक चल पड़ी और छात्रा ने चलती ट्रेन में चढऩे की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ छूट गया। मृतका की पहचान अमृता नायर (21 वर्ष) के रूप में हुई है, जो जयपुर के धावास की रहने वाली थी। वह फेथ इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, बेंगलुरु की सेकंड ईयर की छात्रा थी और अपनी सहेली एंजल थॉमस के साथ ट्रेन में यात्रा कर रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जब ट्रेन ने स्टेशन से चलना शुरू किया, अमृता बोतल लेने के बाद दोबारा ट्रेन में चढऩे की कोशिश कर रही थी लेकिन संतुलन खोने के कारण वह प्लेटफॉर्म के नीचे गिर गई। उसके सिर में गंभीर चोट आई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के दौरान ट्रेन के बी-3 कोच में सवार एक अन्य यात्री, रोशन अली (50 वर्ष) भी घायल हो गए। हादसे के समय सिर और पैर में चोटें लगने के कारण घायल हो गए। उसने छात्रा को पकड़कर ट्रेन में चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन छात्रा का वजन अधिक होने के कारण वह उसे संभाल नहीं सका और दोनों नीचे गिर गए। इसी दौरान छात्रा ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गई, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रेन को चेन पुलिंग के द्वारा रोका गया और रेलवे एवं स्टेशन सुरक्षा कर्मियों ने घायल यात्री को तुरंत अस्पताल पहुंचाया और मृतका को प्लेटफॉर्म से हटाया। इस घटना के कारण ट्रेन 27 मिनट देरी से चली। घटना की जानकारी मिलने के बाद आरपीएफ और जीआरपी ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

छोटा महादेव भोपाली में कावड़िये करेंगे भगवान शिव का अभिषेक

कावड़ यात्रा में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष, केन्द्रीय राज्य मंत्री हुए शामिल

बैतूल। श्री चमत्कारी बालाजी हनुमान मंदिर समिति खंजनपुर द्वारा आयोजित कांवड़ यात्रा में 300 से अधिक शिवभक्तों ने कावड़ यात्रा निकाली। श्रद्धालु जल लेकर पदयात्रा करते हुए छोटा महादेव भोपाली पहुंचेगे, जहां आज भगवान शिव का जलाभिषेक किया जायेगा। कावड़ यात्रा में केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उईके, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल, जन

अभियान परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन नगर, भाजपा जिला अध्यक्ष सुधाकर पवार, जिला पंचायत अध्यक्ष राजा पवार, उपाध्यक्ष हंसराज धुर्वे, भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष महेश्वर सिंह चंदेल, भोला खंडेलवाल, पर्वतराव धोटे भी शामिल हुए। खंजनपुर दुर्गा वार्ड के से शुरू हुई श्री चमत्कारी बालाजी हनुमान मंदिर से शुरू हुई कावड़ यात्रा नागदेव मंदिर, गणेश चौक, शिव मंदिर कोठीबाजार, कमानी गेट होते हुए भोपाली छोटा महादेव के लिए रवाना हुई। कावड़ यात्रा में गुड्डू मिश्रा, पार्षद संतोष भलावी, यशवंत पवार, सुनील नाहारिया सहित शिवभक्त एवं गण्यमान्य गाजे-बाजे के साथ में भोपाली के लिए रवाना हुए। कावड़ यात्रा का जगह-जगह स्वागत किया। इस दौरान कमानी गेट पर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल, जिला भाजपा अध्यक्ष सुधाकर पावर, नगरपालिका अध्यक्ष पार्वती बरसाकर और नवीन तातेड़ विशेष रूप से उपस्थित थे। शर्मा फ्यूल प्वाइंट पर भाजपा नेता सुनील शर्मा और राकेश शर्मा रक्कू ने कांवडियों के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था की।

खेड़ी ताप्ती से आज निकलेगा सैकड़ों कावड़ियों का जत्था

बैतूल। श्री शिव मंदिर उत्सव समिति विनोबा नगर एवं श्री माता मंदिर समिति शंकर नगर बैतूल द्वारा लगातार 5 वे वर्ष निकाली जा रही कावड़ यात्रा में श्रद्धालु कांधे पर कावड़ लेकर खेडी तापी से रवाना होंगे। खेड़ी तापी से निकलने वाली इस कावड़ यात्रा का विभिन्न मार्गों पर स्वागत सत्कार भी किया जाएगा, यात्रा का समापन विनोबा वार्ड स्थित शिव मंदिर में होगा। यह कावड़ यात्रा प्रातः 7 बजे खेड़ी तापी से प्रारंभ होकर पूरे उत्साह और धार्मिक वातावरण के बीच विनोबा वार्ड स्थित श्री शिव मंदिर पहुंचेगी।

सांसद एवं विधायक की जोड़ी ने एक ही दिन में शहरवासियों को दी करोड़ों की सौगात

संयुक्त तहसील भवन का लोकार्पण, पुलिस चौकी का हुआ भूमिपूजन

कई विकास कार्यों एवं सड़कों का हुआ लोकार्पण व भूमिपूजन

संजय द्विवेदी, बैतूल।

भारी व्यस्तता के बीच भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद पहली मर्तबा बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल ने केंद्रीय राज्यमंत्री व क्षैत्रीय सांसद दुर्गादास उईके के साथ रविवार को ताबड़तोड़ भूमिपूजन एवं लोकार्पण कर विभिन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इन लोकार्पण और भूमिपूजन से जहां लोगों को पहले से ज्यादा सुविधाएं तो मिलेगी। वहीं सबसे बड़ी सुविधा के रुप में संयुक्त तहसील कार्यालय का लोकार्पण होने के बाद अब लोगों को राजस्व संबंधित समस्त कार्य एक ही स्थान पर होने की सुविधा भी मिल जाएगी, वहीं सोनाघाटी क्षैत्र में पुलिस चौकी खुलने से फोरलेन के हिस्से की सुरक्षा भी बढ़ेगी। इसके अलावा हेमंत खंडेलवाल एवं डीडी उईके की जोड़ी ने करोड़ों के विकास कार्यो व सड़कों का रविवार को भूमि पूजन किया। श्री उइके और प्रदेश अध्यक्ष श्री खंडेलवाल ने सतपाल आश्रम से इटारसी रोड तक बनने वाली सडक़, नाली और गेट निर्माण कार्य का रविवार को भूमिपूजन किया। वर्षों से वार्डवासी इन विकास कार्यों की मांग कर रहे थे। इस कार्यक्रम को संबोधित करते विधायक श्री खंडेलवाल ने कहा कि वार्ड में अब 48 लाख रुपए की लागत से सडक़, 38 लाख से नाली और 5 लाख रुपए से गेट का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने नगर पालिका सीएमओ को निर्देश दिए कि कार्य पूरी गुणवत्ता से हो और सडक़ चौड़ी बनवाई जाए। साथ ही नालियों को पूरी तरह से कवर्ड करने की बात भी कही। भूमिपूजन के पश्चात अतिथियों ने सतपाल आश्रम पहुंचकर परिसर में पर्यावरण संरक्षण के तहत पौधारोपण किया। इस दौरान सतपालजी महाराज का पूजन और गुरुओं का सम्मान कर आशीर्वाद लिया। इस मौके पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष हंसराज धुर्वे, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती पार्वतीबाई बारस्कर, सुधाकर पवार, पार्षद रघुनाथ लोखंडे सहत नपा अधिकारी सतीश मटसेनिया और बड़ी संख्या में वार्डवासी उपस्थित रहे।

टांगा चौक से न्यू बैतूल स्कूल तक बनेगी सीसी रोड

प्रदेश अध्यक्ष व बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल ने जवाहर वार्ड के तांगा चौक, बाबू चौक से न्यू बैतूल स्कूल तक 2 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाली सीसी सडक़ का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि शहरवासियों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए तांगा स्टैंड, बाबू चौक, न्यू बैतूल स्कूल तक 2 करोड़ से अधिक लागत से सीसी रोड, कन्वर्ट रोड डिवाइडर, सेंट्रल लाइटिंग का निर्माण कार्य होगा। इस दौरान विधायक श्री खंडेलवाल ने गंज मंडी परिसर निर्माण का जिक्र करते हुए बताया कि तकनीकी कारणों और अधिक लागत के चलते कांप्लेक्स निर्माण रुका हुआ था। उन्होंने कहा कि कांप्लेक्स निर्माण के लिए टेंडर जारी हो चुके हैं। शीघ्र ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद दुकानदारों को लागत मूल्य पर दुकानें और उनका मालिकाना हक मिलेगा। वहीं गंज को 30 हजार स्क्वायर फीट की अंडरग्राउंड पार्किंग मिलेगी।

गंज को किया जाएगा व्यवस्थित

भूमिपूजन कार्यक्रम के दौरान विधायक श्री खंडेलवाल ने कहा कि गंज क्षेत्र को विकसित कर पूरी तरह से व्यवस्थित किया जाएगा। आगामी समय में गंज में ओपन ऑडिटोरियम का निर्माण भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सेंट्रल स्कूल से विजय भवन होते हुए बडोरा तक 60 फीट सडक़ निर्माण प्रस्तावित किया गया है। सडक़ के चौड़ीकरण होने से किसी भी दुकानदार का व्यवसाय प्रभावित न हो इसके लिए नगर पालिका द्वारा 5 वर्ष से व्यवसाय कर रहे दुकानदारों का सर्वे किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर में एक भी अतिक्रमण नहीं रहे, लेकिन एक भी अतिक्रमणकारी का व्यवसाय न जाए इसके लिए उन्हें स्थाई दुकान की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी।

पुलिस चौकी की मिली सौगात, केंद्रीय मंत्री डीडी उइके एवं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने किया भूमिपूजन

बैतूल। जिले की ग्राम पंचायत कढ़ाई सोनाघाटी में रविवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पुलिस चौकी की स्थापना के लिए भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्यमंत्री दुर्गादास उइके और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल ने विधिवत पूजन-अर्चन कर भूमि पूजन संपन्न कराया। काफी समय से सोनाघाटी क्षेत्र में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के दृष्टिकोण से पुलिस चौकी की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सतत प्रयासों से यह बहुप्रतीक्षित सौगात अब क्षेत्रवासियों को प्राप्त हुई है। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष राजा पवार, उपाध्यक्ष हंसराज धुर्वे, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती पार्वती बाई बारस्कर, जिला योजना समिति के सदस्य सुधाकर पवार सहित अनेक जनप्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, पुलिस अधीक्षक निश्चल झरिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती कमला जोशी सहित पुलिस विभाग का स्टाफ मौजूद रहा।

6.40 करोड़ की लागत से बने संयुक्त तहसील भवन का लोकार्पण, राजस्व सेवाएं होंगी सुगम

बैतूल। जिले में 6 करोड़ 40 लाख रुपये की लागत से नवनिर्मित संयुक्त तहसील भवन का लोकार्पण केंद्रीय राज्यमंत्री दुर्गादास उइके एवं प्रदेश अध्यक्ष व बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल के कर कमलों से रविवार को संपन्न हुआ। इस अवसर पर दोनों जनप्रतिनिधियों ने नवीन भवन में स्थापित कार्यालयों का अवलोकन कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली।

नवनिर्मित भवन से आमजन को राजस्व सेवाओं का त्वरित और सुगम लाभ मिलेगा। समारोह को संबोधित करते हुए बैतूल विधायक खंडेलवाल ने कहा कि कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के नेतृत्व में बैतूल तहसील में सुधार आएगा। तहसील भवन बनने से अब बैतूल तहसील के 188 ग्रामों की 3 लाख 57 हजार 607 आबादी कवर होगी। केंद्रीय मंत्री श्री उइके ने कहा कि बैतूल विधायक श्री हेमंत खंडेलवाल के प्रयासों से जिला मुख्यालय बैतूल में संयुक्त तहसील भवन बनने से नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र के राजस्व प्रकरणों का निराकरण होगा। साथ ही ग्रामीणों को पार्किंग सहित अन्य असुविधाओं का सामना अब नहीं करना पड़ेगा। लोकार्पण समारोह में मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष एवं राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त मोहन नागर, जिला पंचायत अध्यक्ष राजा पवार, उपाध्यक्ष हंसराज धुर्वे, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती पार्वती बाई बारस्कर, सुधाकर पवार सहित अन्य जनप्रतिनिधि, कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, पुलिस अधीक्षक निश्चल झारिया, एसडीएम मकसूद अहमद, तहसीलदार गोवर्धन पाठे समेत अनेक अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

30 करोड़ की लागत से लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम का होगा कायाकल्प

बैतूल। प्रदेश अध्यक्ष एवं बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल ने रविवार को प्रशासनिक अधिकारियों के साथ लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, शिक्षा विभाग की रिक्त भूमि और नेहरू युवा केंद्र का जायजा लिया। विधायक श्री खंडेलवाल ने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने और युवाओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बैतूल में हर खेल के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के मैदान तैयार किए जाएंगे। इन खेलों में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट और फुटबॉल शामिल हैं। इसके साथ ही फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट के लिए आधुनिक टर्फ ग्राउंड भी विकसित किए जाएंगे। 30 करोड़ की लागत से लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम का कायाकल्प किया जाएगा। विधायक श्री खंडेलवाल ने

अधिकारियों को निर्देश दिए कि बैतूल जिले को खेलों का हब बनाने के लिए एक समग्र योजना तैयार की जाए, जिसमें सभी प्रमुख खेलों के लिए अलग-अलग ग्राउंड और सुविधाएं शामिल हों। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में निरीक्षण के दौरान विधायक श्री खंडेलवाल ने क्रिकेट खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उनके साथ फोटो भी ली। उन्होंने कहा कि आज के युवाओं में अपार प्रतिभा है, जिसे निखारने के लिए उचित अधोसंरचना और संसाधनों की आवश्यकता है। हमारा उद्देश्य है कि बैतूल के खिलाड़ी किसी भी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में पीछे न रहें। उन्हें वही सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो महानगरों में खिलाड़ियों को मिलती हैं। प्रदेश अध्यक्ष व बैतूल विधायक श्री खंडेलवाल ने जिला मुख्यालय स्थित पुलिस ग्राउंड का भी निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक श्री खंडेलवाल ने पुलिस ग्राउंड में रबर ट्रैकिंग, लाइटिंग और बाउंड्री वॉल के रिनोवेशन के निर्देश दिए। इस अवसर पर कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, पुलिस अधीक्षक निश्चल झारिया, नगर पालिका सीएमओ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

लायंस क्लब महक ने ग्राम पांगरा में चलाया पौधारोपण अभियान

बैतूल। लायंस क्लब बैतूल महक के द्वारा ग्राम पांगरा में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्लब की सह-कोषाध्यक्ष लायन सपना सीकेरा ने पर्यावरणीय संरक्षण की दिशा में विशेष पहल करते हुए अपनी ओर से 75 पौधे लगवाए। इन पौधों में सहजन, आंवला और नींबू जैसे औषधीय व फलदार वृक्ष शामिल थे।

इस कार्यक्रम में क्लब को विशेष सम्मान तब मिला जब एमजेएफ लायन पी.एस. बग्गा (पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर) एवं लायन रिप्पी बग्गा (एक्सटेंशन चेयरपर्सन) की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम में लायंस क्लब सिटी के अध्यक्ष लायन बी के कुबड़े एवं सचिव लायन शिशिर

चौधरी, लायंस क्लब महक की अध्यक्ष लायन उमा पवार, उपाध्यक्ष लायन रंजना झोड़, कोषाध्यक्ष लायन संध्या बोहरे, सह-सचिव लायन रक्षा अग्रवाल, एलसीआईएफ चेयरपर्सन लायन चंद्रकांता गाकरे, तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लायन सपना सोनी, लायन कंचन आहूजा, एमजेएफ लायन मधुबाला देशमुख उपस्थित रहे। लायंस क्लब अमिगोश से भी इस कार्यक्रम में सहयोग प्राप्त हुआ। क्लब के अध्यक्ष लायन तिलक पगारिया, सचिव लायन अभय माहेश्वरी और कोषाध्यक्ष लायन रोहित थारवानी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। लिओ क्लब से सेक्रेटरी स्वप्निल पवार ने सक्रिय भागीदारी की। इसके अलावा कार्यक्रम में उपसंचालक खनिज मनीष पलेवार एवं प्रतिमा पलेवार, जीएसटी एक्जीक्यूटिव एन के कौशिक एवं श्रीमती नीलम कौशिक, एलआईसी अधिकारी विशाल शर्मा, न्यूमेरोलॉजिस्ट मकेश गाकरे, अनिल पवार सहित अनेक सहयोगीजन उपस्थित रहे।

गायत्री परिवार चला रहा है ऋषियों की परंपरा, वृक्षगंगा अभियान में लगाए 108 पीपल सहित 5000 पौधे

गायत्री परिवार संस्कृति, संस्कार और सेवा का प्रतीक : केंद्रीय मंत्री डीडी उईके

बैतूल/आमला। अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा संचालित वृक्षगंगा अभियान एवं 108 कुण्डीय शक्तिसंवर्धन गायत्री महायज्ञ की पूर्णाहुति आमला रेलवे स्टेडियम परिसर में भव्य रूप से संपन्न हुई। इस अवसर पर केन्द्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास (डीडी) उईके ने सप्तपर्णी का पौधा रोपकर यज्ञ की सफलता के लिए आहुतियाँ अर्पित कीं। उन्होंने कहा कि गायत्री परिवार ऋषियों की संस्कृति और संस्कारों की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। यह संगठन सेवा, समर्पण और सामाजिक चेतना का प्रतीक बन चुका है।

इस अवसर पर आमला विधायक डॉ. योगेश पंडागरे ने कहा कि गायत्री परिवार समाज में व्याप्त कुरीतियों के उन्मूलन, पारिवारिक संस्कारों की पुर्नस्थापना और सामाजिक नवजागरण के लिए उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। उन्होंने वृक्षगंगा अभियान को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रेरणास्पद पहल बताया। कार्यक्रम के दौरान 108 पीपल के पौधों का विशेष रूप से रोपण किया गया। इस अवसर पर एडीआरएम अनिल कुमार पाटिल, नपा अध्यक्ष नितिन गाडरे, स्टेशन प्रबंधक एस.के. गुप्ता, रेलवे अधिकारी मुकेश जोशी एवं दक्षिण कोरिया से आए वैज्ञानिक प्रो. विजय सिंह सोलंकी सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। गायत्री परिवार के जिला समन्वयक डॉ. कैलाश वर्मा ने बताया कि आमला विकासखंड में गायत्री परिवार द्वारा लगभग 5000 पौधों का रोपण किया जाएगा, जिनकी सुरक्षा हेतु ट्रीगार्ड या अन्य संसाधनों का उपयोग किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी गायत्री परिवार के युवा प्रकोष्ठ को सौंपी गई है।

रेलवे स्टेडियम परिसर में सप्तपर्णी, आम, बरगद जैसे पौधों को ट्रीगार्ड से सुरक्षित कर रोपण किया गया। यह कार्य 'तरुपुत्र अभियान' के अंतर्गत हुआ, जिसमें परिजन स्वयं ट्रीगार्ड समर्पित कर पर्यावरण संरक्षण में सहभागी बन रहे हैं। नपा अध्यक्ष नितिन गाडरे ने स्वयं एक पौधा और ट्रीगार्ड लगाकर अभियान में सहभागिता दी। उन्होंने कहा, 'यदि यह परंपरा सतत चलती रही, तो आने वाले 10 वर्षों में आमला हरा-भरा और स्वच्छ नगर के रूप में उभरेगा।' वरिष्ठ अभिवक्ता राजेन्द्र उपाध्याय एवं भाजपा नेता मनोज विश्वकर्मा ने सम्पूर्ण कार्यक्रम में पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण के साथ सामाजिक सहभागिता निभाई, जो प्रशंसनीय रही।

विदेश से भी मिली तकनीकी प्रेरणा और समर्थन- गौरतलब है कि इस अभियान को स्वदेश के साथ-साथ, दक्षिण कोरिया से भी सराहना और तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। दक्षिण कोरिया के सिओल यूनिवर्सिटी में पदस्थ वैज्ञानिक प्रो. विजय सिंह सोलंकी जो अपने गृह नगर के प्रवास पर दक्षिण कोरिया से आए है, ने इस कार्यक्रम में आकर वहां के ÷वीडियो आधारित स्मार्ट प्लांटेशन मॉडल÷ की जानकारी सभी से साझा की, जिसमें कम समय में पौधों को विकसित करने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग कैसे किया जाता है। इस नवाचार को आगे चलकर गायत्री परिवार के वृक्षगंगा अभियान में लागू करने की योजना है, ताकि स्थानीय स्तर पर भी वैश्विक मानकों के अनुरूप पौध संरक्षण किया जा सके। इस महायज्ञ एवं वृक्षगंगा अभियान में बैतूल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक वर्मा, प्रकाश देशमुख, उत्तम जोशी, अमरदीप वर्मी, मंयक मालवीय, सुभाष मालवीय, योगेश साहू, बंधना जोशी, विद्या मालवीय, संगीता मालवीय, डॉ. ज्योति सोलंकी सहित सैकड़ों परिजन एवं नागरिक उपस्थित रहे।

'एक पेड़, माँ के नाम' अभियान के माध्यम से गायत्री परिवार द्वारा पौधारोपण को न केवल एक औपचारिकता, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव और सांस्कृतिक उत्तरदायित्व का प्रतीक बना दिया है।

पत्रकार के प्रयासों से मजदूरों को मिला बकाया भुगतान

भोपाल में दो महीने काम के बाद भी नहीं मिला था मेहनताना

बैतूल/भौंरा। शाहपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत सालीमेट के ग्राम सेमलपुरा के 32 आदिवासी मजदूरों को भोपाल में दो महीने तक कठिन श्रम करने के बावजूद उनका मेहनताना नहीं मिला था। यह मामला उस समय उजागर हुआ, जब भौंरा के वरिष्ठ पत्रकार कैलाश प्रसाद अग्निहोत्री को मजदूरों ने अपनी परेशानी बताई। मजदूरों ने बताया कि वे भोपाल के बंसल हॉस्पिटल के पास फुटपाथ निर्माण कार्य में ठेकेदार सुनील त्यागी के अधीन काम कर रहे थे। उन्हें 500 प्रतिदिन की दर से मजदूरी देने का वादा किया गया था और कहा गया था कि हर 15 दिन में भुगतान किया जाएगा। लेकिन दो महीने तक कार्य कराने के बावजूद मजदूरों को पूरा भुगतान नहीं किया

गया। खर्च के नाम पर कभी-कभी केवल 100 से लेकर 1000 तक की मामूली रकम एडवांस में दी जाती रही। जब मजदूरों को लगातार टाला गया और मेहनताना नहीं मिला, तो उन्होंने भौंरा के पत्रकार कैलाश प्रसाद अग्निहोत्री से संपर्क किया। श्री अग्निहोत्री ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत सक्रियता दिखाई और सभी 32 मजदूरों को भोपाल अपर कलेक्टर से मुलाकात कराई। अपर कलेक्टर ने तुरंत श्रम विभाग की सहायक श्रमायुक्त जास्मीन अली सितारा को फोन पर जानकारी दी और निर्देश दिए। इसके बाद पत्रकार स्वयं सभी मजदूरों को लेकर श्रम विभाग के कार्यालय पहुंचे, जहां सहायक श्रमायुक्त ने मजदूरों की शिकायत सुनी और ठेकेदार सुनील त्यागी को तत्काल कार्यालय बुलाया। विभागीय दबाव और पत्रकार के प्रयासों के चलते दूसरे ही दिन मजदूरों को उनका बकाया भुगतान कराया गया।

संभागीय संयुक्त संचालक ने ली शिक्षा विभाग की बैठक

योजनाओं के सम्बन्ध में दिए महत्तवपूर्ण निर्देश

नर्मदापुरम (निप्र)। संभागीय संयुक्त संचालक लोकशिक्षण नर्मदापुरम संभाग नर्मदापुरम डॉ. मनीष वर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को शिक्षा विभाग जिला नर्मदापुरम की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कक्षा 1 से 12 तक विद्यार्थियों का शत प्रतिशत नामांकन करने का लक्ष्य पूर्ण करने के लिए विकासखंड शिक्षा अधिकारियों, संकुल प्राचार्यों को निर्देशित किया गया। साथ ही निर्देशित किया गया कि विद्यार्थी कक्षा 1 से 12 तक ड्रॉप आउट नहीं हो एक सप्ताह की अवधि में 3.0 पोर्टल पर नामांकन पूर्ण किया जाए। विद्यार्थियों की प्रोफाइल 100त्न अपडेट होना चाहिए।

पुस्तकों का 100प्रतिशत वितरण सुनिश्चित कर विमर्श पर वितरण संख्या अपलोड करे, साइकिलों का वितरण पात्र छात्रों को अति शीघ्र कराया जाए, सभी शिक्षक एवं कर्मचारी निर्धारित समय पर विद्यालयों में उपस्थित हो। प्रार्थना का समय अधिकतम 20 मिनट रखा जाए। जिला शिक्षा अधिकारी, डीपीसी/सहायक संचालक, एडीपीसी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, संकुल प्राचार्य, विकासखंड स्त्रोत समन्वयक, जनशिक्षक लक्ष्यानुरूप सतत विद्यालयों की मॉनिटरिंग करें। श्री वर्मा ने कहा कि प्रत्येक शाला में टाइम टेबल कक्षा बार और शिक्षक बार अनिवार्य रूप से बनाया जाए। कक्षा शिक्षण टाईम टेबल अनुसार शिक्षक कक्षा में जावे। कलेंडर अनुसार पाठ्यक्रम इकाई पूर्ण करे। प्राचार्य कक्षा अवलोकन वॉक चॉक एंड टॉक की तर्ज पर करे। किसी भी विद्यालय में किसी शिक्षक के अनुपस्थित रहने पर कालखंड रिक्त ना रहे। विद्यालय में बच्चों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जावे, विद्यालय में कोई अपराध न हो, बच्चों को स्व अनुशासन रहे।

बाल कैबिनेट का गठन करे। श्री वर्मा ने कहा कि नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक माहौल में बदले। प्रत्येक शिक्षक एवं कर्मचारी की विद्यालय में समय पर उपस्थित रहे। खेल की गतिविधि का एक पीरियड टाइम में टेबल रखे। खेल प्रतियोगिता में प्रतिभाओं को अवसर दे। विद्यालय में उपलब्ध संसाधन मैदान के अनुरूप खेल कराएं। बच्चों से ली गई फीस का लेखा लेसर में लिखना सुनिश्चित करे, बच्चों को रसीद दे एवं पैसा बैंक में जमा करे। कक्षा पांचवी, आठवीं, दसवीं, 12वीं का परीक्षा परिणाम 100त्न किए जाने का पूर्ण प्रयास करें। साथ ही यह सुनिश्चित हो कि हमेशा की तरह नर्मदापुरम जिले में परीक्षा की सुचिता अनवरत रहे। कक्षा 9वी में प्रवेशित छात्रों को बेसलाइन टेस्ट अनिवार्य रूप से हो। अतिथि शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी हो और विभागीय नियमानुसार ही अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। शिक्षा विभाग के सभी लोकसेवक मध्यप्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 का पालन करें।

श्री वर्मा ने निर्देश दिए कि वित्तीय क्रय आदि प्रक्रियाओं में म. प्र. भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015 (यथा संशोधित 2022) का अक्षरशः पालन हो। प्रत्येक लोक सेवक की सेवा पुस्तिका विधिवत संधारित की जाए और सेवा अभिलेख पूर्ण रखे जाएं। विकासखंड स्तर पर जनशिक्षा केंद्र बार जानकारी पूर्ण रखी जाए। विकासखंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा लोक सेवकों के वेतन का भुगतान संकुल प्राचार्यों के माध्यम से उपस्थिति पत्र को प्रमाणित करने के पश्चात ही किया जाए। सभी पात्र लोकसेवकों को क्रमोन्नति वेतनमान और समयमान वेतनमान का भुगतान समय से किया जाए। एक पेड़ मां के नाम प्रत्येक स्कूल अधिक से अधिक पौधें लगाए पोर्टल पर फोटो अपलोड कर प्रमाणपत्र डाउनलोड करे जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं वहां शिक्षक को जवाबदारी दे।

संयुक्त संचालक द्वारा जिले के निर्माणाधीन सांदीपनि विद्यालयों के संदर्भ में डीईओ और सभी सांदीपनी विद्यालयों के प्राचार्यों को उन्होनें निर्देशित किया कि निर्माणाधीन विद्यालय भवनों का निरंतर निरीक्षण करते रहें एवं कार्य शीघ्र पूर्ण कर भवन विभाग को हैंड ओवर करने हेतु निर्माण एजेंसी को कलेक्टर के माध्यम से निर्देशित कराए। साथ ही सांदीपनि विद्यालयों में प्रवेश एवं अध्यापन के संबंध में निर्देशित किया गया कि शासन की मंशा अनुरूप इन विद्यालयों का शैक्षणिक स्तर उत्कृष्ट रहे। अनुरक्षण कार्य एस.एम.डी.सी. के अनुमोदन उपरांत ही कराए। कार्य की पूर्व फोटो एवं बाद की फोटो सुरक्षित रखे. विभागीय आयामों में नर्मदापुरम जिला सदैव प्रथम 10 जिलों में रहे इस हेतु निरंतर दृढ़ता से कार्य करें।

समीक्षा बैठक में संयुक्त संचालक लोक शिक्षण कार्यालय नर्मदापुरम से जिला शिक्षा अधिकारी एस.पी.एस.बिसेन, डीपीसी डॉ राजेश जायसवाल, उपसंचालक श्रीमती ज्योति प्रह्लादी, सहायक संचालक शानू कोरी, परख जैन, ए.डी.पी.सी. राजेश गुप्ता, विनोद तिवारी एपीसी, संभागीय नोडल सांदीपनी विद्यालय सुदीप गौर, डी.एन.व्यास संभागीय आई.टी.सेल समन्वयक, उपस्थित रहे। डीईओ एवं डीपीसी श्री राजेश जायसवाल द्वारा संयुक्त संचालक को आश्वस्त किया कि जिला शैक्षिक गतिविधियों में आपके मार्गदर्शन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगा। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी श्री एसपीएस बिसेन द्वारा जिले में संचालित विद्यालयों एवं परीक्षा परिणाम की जानकारी दी गई तथा डीपीसी डॉ राजेश जायसवाल द्वारा कक्षा 1 से 8 से संबंधित विभागीय जानकारी दी गई।

बैठक में जिला न्यायालय के माननीय न्यायाधीश विजय कुमार पाठक एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय सिंह ने एक पेड़ मां के नाम पौधा रोपण करने के लिए प्रेरित किया एवं जिला न्यायालय से आपेक्षित सहयोग देने को कहा। समीक्षा बैठक की समाप्ति पर डीईओ शत्रुंजय प्रताप सिंह बिसेन द्वारा आभार व्यक्त किया गया।

संक्षिप्त समाचार

बैतूल जिले को लॉ कॉलेज संचालन की मिली अनुमति

प्राचार्य डॉ. मीनाक्षी चौबे ने केंद्रीय मंत्री, प्रभारी मंत्री व जनप्रतिनिधियों का जताया आभार

बैतूल (निप्र)। बैतूल जिले को विधि (लॉ) कॉलेज प्रारंभ करने की अनुमति प्राप्त हो गई है। नोडल प्राचार्य डॉ मीनाक्षी चौबे ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री दुर्गादास उईके, प्रदेश के प्रभारी मंत्री श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल एवं क्षेत्र के सभी विधायकगणों का आभार प्रकट किया गया है। कॉलेज की प्राचार्य डॉ. मीनाक्षी चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष लॉ कॉलेज में 60 सीटों पर प्रवेश की व्यवस्था की गई है। प्रारंभिक चरण में कक्षाओं का संचालन जे एच कॉलेज परिसर स्थित विवेकानंद सभागार में किया जाएगा। लॉ कॉलेज के लिए 9 करोड़ 36 लाख की लगता से नवीन भवन सोनाघाटी में प्रगतिरत है। प्राचार्य डॉ चौबे ने कहा कि यह अनुमति न केवल संस्थान के लिए गर्व की बात है, बल्कि क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए भी एक सुनहरा अवसर प्रदान करेगी। लॉ कॉलेज के शुभारंभ से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम जुड़ेगा तथा स्थानीय छात्र-छात्राओं को कम कीमत पर विधि शिक्षा के लिए अब अन्यत्र नहीं जाना पड़ेगा। डॉ. चौबे ने इस उपलब्धि के लिए सभी जनप्रतिनिधियों, शासन-प्रशासन और शैक्षणिक परिवार के सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया।

कलेक्टर के निर्देशानुसार अवैध मत्स्याखेट पर मछली पालन विभाग की बड़ी कार्यवाही

नर्मदापुरम (निप्र)। कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना के निर्देशानुसार मछली पालन विभाग द्वारा 16 एवं 17 जुलाई 2025 को जिले में अवैध मत्स्याखेट एवं मत्स्य परिवहन के विरुद्ध सघन अभियान चलाया गया। अभियान के अंतर्गत गठित दल द्वारा ग्राम डोंगरवाड़ा, सांवलखेड़ा, आंवलीघाट, खोकसर एवं तालनगरी सहित अन्य क्षेत्रों में कार्रवाई की गई। इस दौरान 790 किलोग्राम मछली जप्त की गई, जिसे विधिसंगत प्रक्रिया के तहत 27 हजार 950 रुपए में नीलाम कर नीलामी में प्राप्त राशि को शासन मद में जमा कराया गया। सहायक संचालक मत्योद्योग ने बताया कि कार्रवाई के दौरान आस-पास के मत्स्याखेट एवं मत्स्य परिवहनकर्ताओं को जिला प्रशासन द्वारा जारी अधिसूचना की जानकारी दी गई तथा अवगत कराया गया कि बंद ऋतु में अवैध मत्स्याखेट या परिवहन करने पर मध्यप्रदेश मत्स्य क्षेत्र अधिनियम 1981 की धारा 5 के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की।

बुजुर्गों की सेहत पर केंद्रित आयुष्मान आरोग्य शिविर का सफल आयोजन

नर्मदापुरम (निप्र)। राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत गत दिवस जिले में बुजुर्ग और उपशामक स्वास्थ्य देखभाल विषय पर आधारित आयुष्मान आरोग्य शिविरों का आयोजन किया गया। यह आयोजन संचालनालय आयुष भोपाल, कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना के निर्देशानुसार एवं प्रभारी जिला आयुष अधिकारी डॉ. एस.आर. करोंजिया के मार्गदर्शन में किया गया। शिविरों का आयोजन जिले के 12 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में किया गया, जिसमें 723 लाभार्थियों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। शिविर के दौरान रोगियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यक औषधियों का वितरण किया गया। शिविर के दौरान मधुमेह, उच्च रक्तचाप एवं हीमोग्लोबिन की निःशुल्क स्क्रीनिंग की गई। इसी प्रकार आमवात, संधिवात (गठिया), प्रोस्टेट, मुख रोग, नेत्र विकार, त्वचा रोग एवं मानसिक विकारों के लिए औषधियाँ प्रदान की गईं। साथ ही रोगियों को योगाभ्यास की जानकारी भी दी गई। औषधीय पौधों जैसे हल्दी, नीम, करी पत्ता, जामुन, सहजन, घृतकुमारी की उपयोगिता बताते हुए नागरिकों को इन्हें अपने घरों में लगाने हेतु प्रेरित किया गया। वर्षा ऋतु जन्य व्याधियों से बचाव एवं उचित आहार-विहार की जानकारी दी गई। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु हल्दी, दालचीनी, अदरक, अजवाइन, सौंफ जैसे घरेलू मसालों के गुण बताए गए। नागरिकों को दिनचर्या, ऋतुचर्या, योग एवं मौसमी बीमारियों से बचाव के विषय में मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया।

संजीवनी क्लिनिक में एक दिवसीय महिला स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न

हरदा (निप्र)। हरदा शहरी क्षेत्र में नवीन मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक विकासनगर वार्ड क्रमांक 34 में गुरूवार को एक दिवसीय महिला स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में डॉ. मंजूषा पराते ने हितग्राहियों का निःशुल्क परीक्षण किया। स्वास्थ्य शिविर में 51 महिला हितग्राहियों का स्वास्थ परीक्षण किया गया। इस दौरान 13 एएनसी का परीक्षण भी किया गया।

''हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वुमेन'' के तहत जागरूकता कार्यक्रम सम्पन्न

हरदा (निप्र)। हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वुमेन कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को परियोजना हरदा ग्रामीण एक व हरदा शहरी सेक्टर 3 में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं व बालिकाओं को महिलाओं से संबंधित अत्याचारों के निवारण के लिये वन स्टॉप सेंटर के संबंध में जानकारी दी गई।

जनसामान्य को शासकीय योजनाओं और सेवाओं का लाभ मिलने में परेशानी न हो : प्रभारी मंत्री श्री पटेल

प्रभारी मंत्री श्री पटेल ने भैंसदेही में की विकास कार्यों की समीक्षा

बैतूल (निप्र)। जनसामान्य को शासकीय योजनाओं और सेवाओं का लाभ मिलने में परेशानी न हो। सभी विभागीय अधिकारी अपनी योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों को और विकास कार्यों को गुणवत्तापूर्ण रूप से समय पर पूर्ण कराएं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों को योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति से नियमित रूप से अवगत कराएं। साथ ही जनप्रतिनिधियों द्वारा बताई जाने वाली समस्याओं और मुद्दों का पूरी गंभीरता और तत्परता से समाधान किया जाएं।

यह निर्देश लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा तथा जिले के प्रभारी मंत्री श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल ने शुक्रवार को जिले के भैंसदेही जनपद कार्यालय में आयोजित विधानसभा स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए। विधानसभा स्तरीय विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के क्रम में शुक्रवार को प्रभारी मंत्री श्री पटेल ने भैंसदेही विधानसभा अंतर्गत भैंसदेही , भीमपुर और आठनेर ब्लॉक में योजनाओं और विकास कार्यों की विभागवार प्रगति की समीक्षा की। साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों के मुद्दों की जानकारी भी ली। बैठक में विधायक भैंसदेही श्री महेंद्र सिंह चौहान, जनपद अध्यक्ष भैंसदेही, श्री राजा ठाकुर, कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, पुलिस अधीक्षक श्री निश्चल झारिया, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अक्षत जैन सहित सभी जिला अधिकारी, ब्लॉक स्तरीय अधिकारी और जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहें।

राजस्व विभाग की समीक्षा कर प्रभारी मंत्री श्री पटेल ने सीमांकन और नक्शा दुरुस्ती के लंबित प्रकरणों का शत प्रतिशत निराकरण करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि सभी पटवारी अपने हलकों पर निर्धारित दिवसों पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहें और इनकी लोकेशन के माध्यम से मॉनिटरिंग भी की जाएं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा कर प्रभारी मंत्री श्री पटेल ने पीएम आवास के शेष लक्ष्य को भी शत प्रतिशत पूर्ण करने के निर्देश तीनों जनपदों के जनपद सीईओ को दिए। उन्होंने कुकरु में आवास निर्माण कार्य में प्रगति लाने के भी निर्देश दिए। विभागीय योजनाओं में अपेक्षाकृत कम प्रगति पर जनपद सीईओ भीमपुर को विशेष ध्यान के लिए निर्देशित किया। प्रभारी मंत्री श्री पटेल ने बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग अंतर्गत स्वनिधि से समृद्धि अभियान, अमृत 2.0, पीएम आवास योजना शहरी इत्यादि योजनाओं की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने पीएम आवास से वंचित हितग्राहियों को धारणाधिकार योजना से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। बैठक में भैंसदेही को 5 कॉलोनियों में मूलभूत विकास नहीं होने की समस्या पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी भैंसदेही को इन कालोनियों के नियमितीकरण संबंधी कार्यवाही कर विकास किए जाने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री श्री पटेल ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा कर निर्देशित किया कि स्वास्थ्य मूलक समस्त योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कराएं। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा टीबी उन्मूलन के लिए टीबी मरीजों को निशुल्क इलाज उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि पीपीपी मॉडल पर बैतूल जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के भी प्रयास किए जा रहे है। उन्होंने झल्लार में चिकित्सकों को कमी की समस्या पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को चिकित्सकों का युक्तियुक्तकरण कर समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सिकलसेल एनीमिया के प्रति स्वास्थ्य, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और महिला बाल विकास विभाग को जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। जर्जर आंगनवाड़ी भवनों संबंधी समस्या पर महिला एवं बाल विकास अधिकारी को इन आंगनवाड़ियों के मरम्मत कराने के निर्देश दिए। साथ ही स्वीकृत आंगनवाड़ियों का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया।

केंद्रीय मंत्री, प्रभारी मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायकगणों ने की विकास कार्यों की समीक्षा

बैतूल (निप्र)। केंद्रीय राज्यमंत्री जनजातीय कार्य श्री दुर्गादास उईके , प्रभारी मंत्री श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल, प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक बैतूल श्री हेमंत खंडेलवाल, विधायक आमला डॉ योगेश पंडाग्रे, विधायक मुलताई श्री चंद्रशेखर देशमुख और विधायक घोड़ाडोंगरी श्रीमती गंगाबाई उईके ने आज कलेक्ट्रेट में कृषि एवं विकास कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक ली। इस दौरान जिला योजना समिति के सदस्य श्री सुधाकर पवार, श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, पुलिस अधीक्षक श्री निश्चल झारिया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहें। कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए गए जिले खाद की आपूर्ति निर्बाध रूप से बनी रहे। किसानों को सुगमता पूर्वक खाद मिले। बैठक में खाद की सतत आपूर्ति को लेकर प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक श्री खंडेलवाल ने प्रमुख सचिव कृषि से चर्चा कर जिले को सतत खाद की आपूर्ति कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि जिले को शीघ्र 2 रैक खाद की उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही निर्देश दिए गए कि नगद में निजी विक्रेताओं से बिना टैगिंग के किसानों को उर्वरक प्राप्त हो। इसके लिए निजी विक्रेताओं की सतत मॉनिटरिंग भी की जाएं। यूरिया सभी को समय पर मिले इसके लिए उर्वरक केंद्रों में समान रूप से व्यवस्था की जाएं। प्रभारी मंत्री श्री पटेल ने निर्देशित किया कि यूरिया कालाबाजारी न हो। ऐसा करने वालों के विरुद्ध एफआईआर प्रकरण दर्ज किए जाएं। सभी विधायकगणों ने अपने क्षेत्र में यूरिया की कमी वाले स्थानों पर शीघ्र आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के जिला अधिकारियों को विकास कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। लोक निर्माण विभाग को बरसाली मार्ग की समस्या का शीघ्र समाधान कर निर्माण कार्य पूरा करने के कहा गया। साथ ही निर्देशित किया गया कि विकास कार्यों में लेटलतीफी करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएं। नगरीय प्रशासन विभाग की समीक्षा कर परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण को निर्देशित किया गया कि बड़े विकास प्रोजेक्ट को समय पूर्ण कराएं। बताया गया कि जनप्रतिनिधियों द्वारा रविवार को विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया जाएगा।

डेंगू जागरूकता रथ के साथ लार्वा सर्वे अभियान निरंतर जारी

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता के निर्देशन में विदिशा जिले में डेंगू जागरूकता रथ के साथ लार्वा सर्वे अभियान का कार्य सतत जारी है। जिला मलेरिया अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, नर्सिंग कालेज की छात्राऐं, उषा कार्यकर्ता के दल के द्वारा आज विदिशा शहरी क्षेत्र के टीलाखेड़ी में सघन लार्वा सर्वे, आईईसी गतिविधि, डेंगू जागरूकता रथ से प्रचार-प्रसार, फॉगिंग दल के द्वारा कीटनाशक दवा का छिड़काव किया गया। मलेरिया टीम के द्वारा 214 घरों का सघन लार्वा सर्वे किया गया। जिसमें 22 घरों में लार्वा पाया गया। कीटनाशक दवा के द्वारा नष्ट कराया गया। जनसमुदाय से अपील है की वह अपने घर के सभी पानी के कंटेनर, कूलर, फ्रिज ,टांके टंकिया, टायर को प्रति सप्ताह जांच ले की एडीज मच्छर के लार्वा तो नही पनप रहे, व खाली कर सफाई कर दें। पानी के बड़े कंटेनर जिनकी सफाई व ढांकना संभव न हो तो उनमें मीठा तेल प्रति सप्ताह डालें। मच्छरों के काटने से स्वयं बचाव करे, पूरे शरीर ढकने वाले कपड़े पहने, दिन के समय बच्चों व वृद्धों को मच्छरदानी के अंदर सोने की सलाह दी जाए, मॉस्किटो कॉइल का उपयोग करे, शाम के समय नीम पत्तियों का धुआं करे।

कलेक्टर ने एनआईएमएचआर, संकल्प वृद्धाश्रम और नशामुक्ति केंद्र का किया निरीक्षण

नशे को खत्म करके किया जा सकता है एक स्वस्थ समाज का निर्माण - कलेक्टर

सीहोर (निप्र)। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने सीहोर स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान, संकल्प वृद्धाश्रम और नशामुक्ति केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संस्थानों के स्टॉफ से चर्चा की और यहां संचालित सेवाओं की गुणवत्ता, व्यवस्थाओं और सुविधाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी ली। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान (एनआईएमएचआर) के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने संबंधित अधिकारियों और स्टॉफ के साथ बैठक आयोजित कर संस्थान की कार्यप्रणाली की जानकारी ली और रोगियों को और बेहतर वातावरण देने के लिए कुछ अहम सुझाव भी दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री बालागुरू के. को जानकारी दी गई कि यह भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन संचालित एक संस्थान है। यह देश का पहला ऐसा संस्थान है जो मानसिक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास, शिक्षा, प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों में विशेष भूमिका निभा रहा है। यहाँ पर मनोचिकित्सक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, समाजसेवी कार्यकर्ता, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और अन्य विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध हैं। इसके साथ ही इस संस्थान में पुनर्वास संबंधी अनेक पाठ्यक्रम भी संचालित हैं। संकल्प वृद्धाश्रम एवं नशामुक्ति केंद्र के निरीक्षण के दौरान उन्होंने यहां निवासरत वृद्धजनों से संवाद किया और उनसे चर्चा कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने संस्थान में बुजुर्गों की देखभाल, स्वास्थ्य सेवाएं, मनोरंजन और सामाजिक सहभागिता के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंनें नशामुक्ति केंद्र में रह रहे व्यक्तियों से भी संवाद किया और नशे को त्यागने के लिए प्रेरित भी किया। उन्होंने कहा कि नशा एक सामाजिक बुराई है, नशे से स्वयं एवं अपने समुदाय को बचाएं। नशे को खत्म करके एक स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सकता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि संस्थानों में निवासरत प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा पूर्ण जीवन, समुचित देखभाल और मानसिक संबल मिल सके, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जाएं। निरीक्षण के दौरान सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के उप संचालक श्री महेश यादव, एनआईएमएचआर के डॉ अंकित चौधरी, श्री आरके नागर, श्री अभिषेक मिश्रा, डॉ नित्यानंद, संकल्प वृद्धाश्रम के श्री राहुल सिंह सहित संबंधित अधिकारी एवं स्टॉफ उपस्थित थे।

प्री-नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट 2022 का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

109 छात्राओं ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर की

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश की नर्सिंग छात्राओं का प्री-नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट (पीएनएसटी)-2022 से जुड़ा मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। परीक्षा देने के 2 साल बाद भी दाखिला न मिल पाने से क्षुब्ध 109 छात्राओं ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की है। यह याचिका मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देती है, जिसमें परीक्षा परिणाम जारी करने की अनुमति तो दी गई, लेकिन प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं कराई गई। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला वरिष्ठ अधिवक्ता वरुण चोपड़ा की अगुवाई में लड़ा जाएगा।

दो साल से अटका भविष्य, खाली पड़ी हैं सरकारी सीटें- एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने बताया कि परीक्षा का आयोजन कर्मचारी चयन मंडल (पूर्व व्यापम/ईएसबी) ने जून 2023 में कराया था। लेकिन परिणाम पर रोक लगा दी गई थी। 27 मार्च 2025 को हाईकोर्ट ने परिणाम जारी करने का आदेश तो दे दिया, लेकिन अब तक काउंसलिंग शुरू नहीं की गई।

परमार ने बताया, 60 हजार से ज्यादा छात्राओं ने परीक्षा दी थी, लेकिन सरकार की लापरवाही और चिकित्सा शिक्षा विभाग की चुप्पी के कारण अब तक एक भी प्रवेश नहीं हुआ है। यह छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ है। छात्राएं दो वर्षों से संघर्ष कर रही हैं। सरकार की चुप्पी और विभागों की निष्क्रियता से छात्राओं का भविष्य अधर में है। अब सुप्रीम कोर्ट से न्याय की आस है।

सुप्रीम कोर्ट में 6 संस्थाओं को बनाया पक्षकार- इस याचिका में मध्यप्रदेश शासन, संचालक चिकित्सा शिक्षा, एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, कर्मचारी चयन मंडल और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज एसोसिएशन को पक्षकार बनाया गया है। छात्राओं की मांग है कि जल्द से जल्द काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर उन्हें नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश दिया जाए।

एनएसयूआई ज़िला अध्यक्ष अक्षय तोमर ने कहा कि शासकीय नर्सिंग कॉलेजों की सीटें खाली पड़ी हैं, लेकिन छात्राएं दर-दर भटक रही हैं। हमने मुख्यमंत्री से लेकर उपमुख्यमंत्री तक ज्ञापन दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब सुप्रीम कोर्ट से ही न्याय की उम्मीद है।

सिर्फ परिणाम से कुछ नहीं हुआ, हमें प्रवेश चाहिए

परिणाम जारी होने के बावजूद छात्राओं को कोई राहत नहीं मिली। छात्रा रविना सूर्यवंशी ने बताया, हमने पीएनएसटी-2022 की परीक्षा दी थी। हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, जिससे रिजल्ट दो साल तक लटका रहा। अब जब रिजल्ट आया है तो भी प्रवेश की कोई प्रक्रिया नहीं शुरू हुई। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है?

मांडू पहुंचेंगे कांग्रेस विधायक, आज से होगी ट्रेनिंग

तन्खा बताएंगे झूठे मुकदमों से निपटने के दांव-पेंच; राहुल गांधी और कमलनाथ वर्चुअली जुड़ेंगे

भोपाल (नप्र)। धार जिले के मांडू में सोमवार से कांग्रेस विधायकों की दो दिनों तक की ट्रेनिंग होगी। 20 जुलाई तक की रात तक सभी विधायक मांडू पहुंचेंगे। सोमवार और मंगलवार को आयोजित इस प्रशिक्षण में करीब 10 सत्र होंगे, जिनमें नेता और विषय-विशेषज्ञ (एक्सपर्ट) विधायकों को संबोधित करेंगे।

21 जुलाई से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। इसी कारण राहुल गांधी इस प्रशिक्षण शिविर में शामिल नहीं हो पाएंगे। 21 या 22 जुलाई को किसी भी दिन राहुल गांधी वर्चुअली जुड़कर विधायकों को संबोधित कर सकते हैं।

21 जुलाई पहला दिन

सुबह 10 बजेः उद्घाटन-नव संकल्प शिविर के उद्घाटन सत्र की शुरुआत ध्वजारोहण और सेवा दल द्वारा राष्ट्रगान से होगी। 10:15 बजे से स्वागत सत्र (45 मिनट)- इस सत्र में प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी और वरिष्ठ नेता गण शिविर के बारे में परिचयात्मक जानकारी देंगे।

तन्खा बताएंगे, फर्जी मुकदमों से कैसे निपटें?

सुबह 11 बजेः मोटिवेशनल स्पीकर सोनू शर्मा विधायकों को जनप्रतिनिधि की भूमिका, नेतृत्व, अनुशासन और संगठनात्मक एकता पर संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजेः राज्यसभा सांसद और सीनियर एडवोकेट विवेक तन्खा फर्जी मुकदमों और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग पर संवैधानिक प्रतिरोध के उपाय बताएंगे।

कमलनाथ बताएंगे आर्थिक नीति- पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ वर्चुअली जुड़कर एक सत्र को संबोधित करेंगे। इस सत्र में वे मध्यप्रदेश का भविष्य और आर्थिक नीति विषय पर प्रदेश की आर्थिक चुनौतियों, अवसरों और विकास की रूपरेखा पर अपना वक्तव्य देंगे।दोपहर एक बजे से 45 मिनट का लंच ब्रेक होगा। 21 या 22 जुलाई को राहुल गांधी वर्चुअली जुड़कर विधायकों को संबोधित कर सकते हैं।

पवन खेड़ा बताएंगे नैरेटिव बिल्डिंग के गुर- 1:45 बजे लंच ब्रेक के बाद कांग्रेस के मीडिया और कम्युनिकेशन विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन खेड़ा मीडिया मैनेजमेंट के गुर सिखाएंगे। विधायकों को वे यह बताएंगे कि नैरेटिव सेट करने के लिए कम्युनिकेशन के माध्यम से कांग्रेस की विचारधारा को मजबूती से कैसे प्रस्तुत किया जाए।

विधानसभा के पूर्व पीएस बताएंगे सत्ता पक्ष पर कैसे प्रहार करें?

2:15 बजे से शुरू होने वाले सत्र में विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव भगवानदेव इसराणी विधायकों को सत्ता पक्ष पर रणनीतिक प्रहार की रणनीति बताएंगे। सरकार की विफलताओं पर आरटीआई, ऑडिट रिपोर्ट और विधानसभा के नियमों के जरिए घेरने की बारीकियों को बताएंगे।

10-10 विधायकों के ग्रुप बनाकर होगी चर्चा

दोपहर 3 से 4 बजे के बीच 10-10 विधायकों के ग्रुप बनाकर समूह चर्चाएं होगी।

वरिष्ठ नेताओं और विशेषज्ञों के साथ बनेगी मिशन 2028 की रणनीति - नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार

धार। मध्यप्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आज धार में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस के नव संकल्प शिविर के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की। श्री सिंघार ने बताया कि धार जिले के मांडू में 21 और 22 जुलाई को कांग्रेस विधायक दल की ओर से नव संकल्प शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस दो दिवसीय शिविर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राजनीतिक विशेषज्ञ और प्रेरक वक्ता विधायकों के साथ गहन चिंतन कर अपने अनुभव साझा करेंगे।

डॉ. अंबेडकर सामुदायिक भवन में महिला सुरक्षा और शराबबंदी की मांग पर महिला सम्मेलन आयोजित

भोपाल (नप्र)। प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों पर बढ़ते अपराधों और शराबबंदी की मांग को लेकर ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की भोपाल जिला समिति द्वारा आगामी 20 जुलाई (रविवार) को द्वितीय जिला स्तरीय महिला सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। यह सम्मेलन डॉ. अंबेडकर सामुदायिक भवन, ओल्ड सुभाष नगर, अप्सरा टॉकीज के पास, भोपाल में दोपहर 12 बजे से आयोजित होगा। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता होंगी रचना अग्रवाल, जो एआईएमएसएस द्धस्स्र मध्यप्रदेश की राज्य सचिव हैं, वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता ऋतु श्रीवास्तव, अध्यक्ष, एआईएमएसएस भोपाल जिला समिति करेंगी।

पुष्य नक्षत्र में सवार होगी वर्षा

मेष वाहन पर आएंगे मेघ, राजनीतिक उथल-पुथल महंगाई और संक्रमण रोगों की भी आशंका

भोपाल (नप्र)। 20 जुलाई से वर्षा का प्रवेश पुष्य नक्षत्र में हो गया। भारतीय ज्योतिषशास्त्र में वर्षा के आठ नक्षत्रों में पुष्य को तीसरा और अत्यंत प्रभावशाली नक्षत्र माना गया है। ज्योतिष मठ संस्थान के पं. विनोद गौतम के अनुसार, 20 जुलाई से 3 अगस्त तक वर्षा पुष्य नक्षत्र के प्रभाव में होगी। इस नक्षत्र की वर्षा मेष वाहन, जला नाड़ी व चंद्र-चंद्र योग के कारण अच्छी मानी जा रही है। इसके चलते आगामी दिनों में अच्छी और संतुलित वर्षा के संकेत हैं।

पं. गौतम ने बताया कि मेघमाला ग्रंथ में वर्णित पुष्य नक्षत्र की स्थिति के अनुसार, जब इसमें केवल सूर्य गतिमान रहता है, तब वर्षा की संभावना प्रबल हो जाती है। हालांकि ग्रहों की स्थिति यह भी इंगित कर रही है कि सूर्य-बुध का योग कर्क राशि में तथा मंगल-केतु का योग सिंह राशि में होने से कुछ समय के लिए वर्षा में बाधा भी आ सकती है।

कर्क संक्रांति के प्रभाव भी दिखेंगे

पं. गौतम के अनुसार, वर्तमान समय में कर्क संक्रांति का असर भी मौसम और राजनीति पर स्पष्ट दिखाई देगा। पूर्वोत्तर भारत में भारी वर्षा से नुकसान की संभावना है। वहीं सिंह राशि में मंगल-केतु की युति राजनीतिक अस्थिरता और विवादों की स्थिति निर्मित कर सकती है। यह स्थिति कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगी।

मेघमाला ग्रंथ में वर्णित पुष्य नक्षत्र की स्थिति के अनुसार, जब इसमें केवल सूर्य गतिमान रहता है, तब वर्षा की संभावना प्रबल हो जाती है।

महंगाई और रोग बढ़ने के संकेत

शेयर बाजार में तेज उतार-चढ़ाव के साथ ही सोना-चांदी और अन्य कीमती धातुओं में कीमतें बढ़ सकती हैं। मंगल-केतु के प्रभाव से देश में संक्रमण रोगों में भी वृद्धि की आशंका जताई गई है। हालांकि पं. गौतम यह भी कहते हैं कि बुद्धिजीवियों और शिक्षा जगत के लिए यह समय शुभ संकेत दे रहा है। अगस्त में जब सूर्य और बुध सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, तब बुधादित्य योग का निर्माण होगा, जो सकारात्मक और ऊर्जावान प्रभाव देगा।

24 दिन तक शेयर बाजार में रहेगी उथल-पुथल

18 जुलाई को सुबह 7:50 बजे से व्यापार जगत के प्रमुख ग्रह बुध वक्री चाल में आ जाएंगे। ज्योतिष मठ संस्थान नेहरू नगर के आचार्य पंडित विनोद गौतम के अनुसार बुध 24 दिनों तक वक्री रहेंगे, जिसका सीधा असर शेयर बाजार, विदेशी व्यापार, संचार और तकनीकी क्षेत्रों पर दिखेगा। बुध के वक्री होने से व्यापार जगत में व्यापक उथल-पुथल की संभावना जताई गई है। कई देशों द्वारा टैरिफ नियमों में बदलाव कर व्यापारिक दबाव बनाया जा सकता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अस्थिरता बढ़ सकती है। हालांकि भारत को इस खींचतान से अपेक्षाकृत सुरक्षित बताया गया है।

नौसेना प्रमुख बोले- अगले 22 साल भारत के लिए निर्णायक

रीवा में कहा- भारत इकलौता राष्ट्र, जिसके नाम पर एक पूरा महासागर है

रीवा (नप्र)। भारत दुनिया का इकलौता राष्ट्र है, जिसके नाम पर एक पूरा महासागर है, जिसे हिंद महासागर के नाम से जाना जाता है। दुनिया में कोई और राष्ट्र ऐसा नहीं। राष्ट्र को आगे बढ़ाना और उसकी प्रगति में सहभागी बनना हम सब की जिम्मेदारी है। आने वाले 22 साल भारत के लिए बेहद निर्णायक हैं, क्योंकि यही वो समय है जब देश की युवा पीढ़ी भारत के भविष्य को गढ़ेगी।

यह बात देश के नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने कही। वे शनिवार को रीवा स्थित ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय (टीआरएस कॉलेज) में 'युवा अभिप्रेरणा कार्यक्रम' में बोल रहे थे।

भोपाल में बीई स्पाइन सर्जरी पर दो दिवसीय कार्यशाला

आधुनिक तकनीक पर देशभर से आए विशेषज्ञों ने गांधी मेडिकल कॉलेज में दिए टिप्स

भोपाल (नप्र)। गांधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल के ऑर्थोपेडिक्स विभाग में यूनिलेटरल बाइपोर्टल एंडोस्कोपिक (यूबीई) स्पाइन सर्जरी पर दो दिवसीय सीएमई एवं हैंड्स-ऑन कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह प्रदेश में इस तकनीक पर आयोजित होने वाली पहली कार्यशाला रही। जिसमें मध्यप्रदेश सहित देशभर से 100 से अधिक युवा और अनुभवी सर्जनों ने भाग लिया।

इस कार्यशाला में सर्जनों को यूबीई तकनीक के माध्यम से कम से कम चीरा लगाकर रीढ़ की सर्जरी करने का प्रशिक्षण दिया गया। इस तकनीक की विशेषता है कम रक्तस्राव, कम जटिलताएं, रोगी का जल्दी स्वस्थ होना और शीघ्र अस्पताल से छुट्टी मिलना।

कार्यशाला में प्रशिक्षण देने के लिए देश के प्रसिद्ध स्पाइन सर्जन भोपाल पहुंचे। इनमें डॉ. मैल्कम पेस्टोंजी (मुंबई), डॉ. अश्विन कुमार खंडगे (पुणे), डॉ. अंकुर गुप्ता (जयपुर), डॉ. स्वप्निल हजारे (नागपुर), डॉ. वी. सेल्विन प्रभाकर (चेन्नई) और डॉ. एडम तेजा (जबलपुर) शामिल रहे।

इन विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को एंडोस्कोपिक सर्जरी की बारीकियों और तकनीकी पहलुओं की लाइव डेमो व थ्योरी से जानकारी दी। गांधी मेडिकल कॉलेज की डीन डॉ. कविता एन. सिंह ने बताया कि जीएमसी भोपाल प्रदेश का पहला सरकारी संस्थान है। जहां पर यह आधुनिक तकनीक अपनाई गई है। इससे प्रदेश के मरीजों को अब अत्याधुनिक रीढ़ की हड्डी के उपचार की सुविधा सुलभ होगी।

मेडिकल सुप्रींटेंडेंट डॉ. सुनीत टंडन ने कहा कि प्रतिभागियों का उत्साह देखने लायक था। यह कार्यशाला सफल रही और अगले साल इसे और बड़े स्तर पर आयोजित किया जाएगा। ऑर्थोपेडिक्स विभागाध्यक्ष डॉ. आशीष गोहिया ने बताया कि जीएमसी का रीजनल स्पाइन इंजरी सेंटर लगातार उन्नत सर्जिकल तकनीकों को अपनाते हुए मरीजों की सेवा कर रहा है।

एंडोस्कोपी तकनीक के जुड़ने से यह केंद्र अब और प्रभावी रूप से कार्य कर सकेगा। वरिष्ठ स्पाइन सर्जन और सह-संयोजक डॉ. राहुल वर्मा ने कहा, युवा सर्जनों को इस क्षेत्र में प्रशिक्षित करना समय की मांग है। इससे न केवल इलाज की गुणवत्ता बढ़ेगी बल्कि रोगियों को भी कम दर्द और जल्दी रिकवरी का लाभ मिलेगा।

कही-सुनी

रवि भोई

(लेखक पत्रिका समवेत सृजन के प्रबंध संपादक और स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

अब क्या बारी भूपेश बघेल की ?

शराब घोटाले मामले में ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया है। इस कारण लोग अब चर्चा करने लगे हैं कि क्या अब ईडी के निशाने पर भूपेश बघेल हैं। अब तक ईडी भूपेश बघेल के घर पर दो बार छापे की कार्रवाई कर चुकी है। पहली बार के छापे में कुछ नगद भी बरामद किया गया था। 18 जुलाई को छापे के बाद उनके पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया। 2018 से 2023 तक कांग्रेस राज के मुखिया रहे भूपेश बघेल सीडी कांड की गर्माहट के बाद भारी बहुमत के साथ सत्ता में आए थे। कोल स्कैम, शराब घोटाला, महादेव एप,पीएससी भर्ती में गड़बड़ी के आरोपों के दलदल में समा कर भूपेश बघेल ने सत्ता गंवा दी। भूपेश बघेल के आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा शराब घोटाले के आरोप में पिछले कई महीनों से बंद हैं। कांग्रेस राज में भूपेश बघेल के करीबी रहे आईएएस अफसर अनिल टुटेजा भी शराब कांड में आरोपी हैं और जेल में हैं। भूपेश बघेल के करीबी रहे कई लोग इन दिनों सलाखों के पीछे हैं ,इस कारण लोग भूपेश बघेल के सिर पर भी खतरा मंडराता देख रहे हैं। वैसे भूपेश के सत्ता में रहते ही राज्य में ईडी की इंट्री हो गई थी और अफसर-कारोबारी जेल चले गए थे। भ्रष्टाचार के आरोप में उनकी काफी करीबी रही सौम्या चौरसिया कई महीनों तक जेल में रही। कांग्रेस राज के कारनामों के चलते दो आईएएस अफसर समीर विश्नोई और रानू साहू भी जेल की चक्की पीस चुके हैं। भूपेश राज में सुर्ख़ियों में रहे कारोबारी सूर्यकांत तिवारी अब भी सलाखों के पीछे हैं। शराब घोटाले की जाँच ईडी के साथ ईओडब्ल्यू भी कर रही है। भूपेश राज में शराब सप्लाई में करीब 3200 करोड़ के घपले-घोटाले का अंदेशा है। शराब कांड की जद में 29 आबकारी अधिकारी भी आ गए हैं, जिन्हें विष्णुदेव साय की सरकार ने सस्पेंड कर दिया है और अब वे गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालतों के दरवाजे सिर-पैर रगड़ रहे हैं। शराब से छत्तीसगढ़ सरकार को काफी राजस्व मिलता है, तो वहीं राजस्व उगाही में छेद ही छेद भी हैं। इस कारण यह बड़ा घोटाला है। अब एजेंसियां घोटाले की तह तक पहुँचने की कोशिश कर रही हैं। इस कोशिश में कई मछलियां भी पकड़ी जा रही है, पर भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य की गिरफ्तारी से कांग्रेस को सिर उठाने का मौका मिल गया है। इस गिरफ्तारी से आने वाले कई दिनों तक राजनीतिक गर्माहट तो बनी रहेगी, साथ में इसके दूरगामी परिणाम भी जनता को देखने को मिल सकता है।

निगम-मंडलों में अध्यक्ष और एमडी घमासान: कहते हैं राज्य के कई निगम-मंडलों में अध्यक्ष और प्रबंध संचालकों के बीच घमासान शुरू हो गया है। विष्णुदेव साय की सरकार ने कुछ महीने पहले ही निगम-मंडलों में अध्यक्षों की नियुक्ति की है। कुछ महीनों में ही कई निगम-मंडल बेपटरी हो गए हैं। बताते हैं एक मंडल में अध्यक्ष और प्रबंध संचालक के बीच बातचीत ही बंद हो गई है। एक निगम में अध्यक्ष के निर्देशों का पालन प्रबंध संचालक नहीं कर रहे, इस कारण विवाद की स्थिति हैं। कुछ निगम-मंडल अध्यक्ष अपने प्रबंध संचालक की कार्यशैली से दुखी हैं। कहा जाता है कि निगम-मंडलों में अध्यक्षों के पास कोई ख़ास अधिकार नहीं हैं। संचालक मंडल के बैठक की अध्यक्षता के अलावा उन्हें कोई वित्तीय अधिकार नहीं हैं। चर्चा है कि अधिकारों को लेकर ही अध्यक्ष और प्रबंध संचालकों के बीच छत्तीस का आंकड़ा बना हुआ है।

ऋचा शर्मा के लिए लाबिंग: चर्चा है कि आईएएस अफसरों की एक लॉबी 1992 बैच के आईएएस अफसर सुब्रत साहू को मुख्य सचिव नहीं बनने देना चाहती। बताते हैं कि लॉबी ने सुब्रत साहू के मुकाबले अब 1994 बैच की आईएएस अफसर ऋचा शर्मा को प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया है। बताते हैं इस लॉबी ने पहले 1994 बैच के ही आईएएस मनोज पिंगुआ को आगे किया था। खबर है कि पिछले दिनों इस लॉबी से जुड़े एक अफसर ने ऋचा शर्मा को अगला मुख्य सचिव बनाने का सुझाव भाजपा संगठन से जुड़े एक उच्च पदाधिकारी को दिया। अब देखते हैं 30 सितंबर के बाद क्या होता है? भारत सरकार ने अमिताभ जैन को तीन महीने का एक्सटेंशन दिया है। ऐसे में 30 सितंबर तक तो अमिताभ जैन मुख्य सचिव रहेंगे।

हिमांशु गुप्ता का वरिष्ठता क्रम क्या होगा: कहते हैं भारत सरकार ने पिछले हफ्ते छत्तीसगढ़ में डीजी का एक पद और स्वीकृत कर दिया। बताते हैं यह सांख्येत्तर पद 1994 बैच के आईपीएस हिमांशु गुप्ता के लिए स्वीकृत हुआ है। छत्तीसगढ़ में डीजी के तीन पद थे। 1994 बैच के आईपीएस जीपी सिंह की बहाली और प्रमोशन के पहले हिमांशु गुप्ता डीजी प्रमोट हो गए थे। जीपी सिंह उनसे वरिष्ठ हैं, इस नाते जब जीपी सिंह को बहाल कर डीजी बनाया गया तो हिमांशु गुप्ता पीछे हो गए और बिना पद के डीजी बने रहे। सरकार ने अभी तक जीपी सिंह को कोई चार्ज नहीं दिया है। सिंह और गुप्ता के अलावा अरुणदेव गौतम और पवनदेव भी डीजी हैं। संघ लोकसेवा आयोग ने स्थायी डीजीपी के लिए अरुणदेव गौतम और हिमांशु गुप्ता के नाम का पैनल राज्य शासन को भेजा हुआ है। इस कारण चर्चा शुरू हो गई है कि डीजी के पदक्रम में हिमांशु गुप्ता का नाम अरुणदेव गौतम के बाद होगा या जीपी सिंह के बाद।

नेताजी की डिमांड से परेशान कारोबारी: चर्चा है कि एक नेताजी ने कारोबार करने वालों के सामने नई फरमाइश रख दी है। इससे कारोबारी परेशान हो गए हैं। बताते हैं कि नेताजी को जुम्मा-जुम्मा हुए सरकारी पद मिला है। सरकारी पद मिलते ही नेताजी को पर लगा है। खबर है कि कारोबारी पहले ही कुछ लोगों को भेंट-चढ़ावा दे चुके हैं, अब नेताजी अपना हिस्सा मांग रहे हैं। नेताजी ने साफ़-साफ़ कह दिया कि उनको तो उनका हिस्सा चाहिए। नेताजी पहले भी भाजपा राज में सरकारी पद पर रह चुके हैं।

चर्चा में रेरा अध्यक्ष: मेडिकल कालेज मान्यता मुद्दे में एफआईआर के बाद छत्तीसगढ़ रेरा के अध्यक्ष संजय शुक्ला चर्चा में हैं। एफआईआर के बाद संजय शुक्ला के कदम का लोगों को इंतजार है। कहते हैं सरकार रेरा अध्यक्ष को हटा तो सकती है, पर प्रक्रिया लंबी है। हटाने से पहले सरकार को रेरा अध्यक्ष पर लगे आरोपों की हाईकोर्ट के जज से जांच करानी पड़ेगी। रेरा न्यायिक संस्था जैसी है। रेरा अध्यक्ष पद पर रिटायर्ड आईएफएस अफसर संजय शुक्ला की नियुक्ति कांग्रेस शासन में हुई थी। संजय शुक्ला छत्तीसगढ़ रेरा के दूसरे अध्यक्ष हैं। पहले अध्यक्ष रिटायर्ड मुख्य सचिव विवेक ढांड थे। विवेक ढांड की नियुक्ति तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने की थी।

बदले जाएंगे कुछ कलेक्टर: चर्चा है कि जुलाई के अंतिम या अगस्त के पहले सप्ताह में 4-5 जिलों के कलेक्टर बदले जाएंगे। खबर है कि बस्तर संभाग के एक-दो दुर्ग संभाग का एक, सरगुजा संभाग का एक कलेक्टर बदला जा सकता है। बिलासपुर संभाग में कुछ हेरफेर हो सकता है। कलेक्टरों की पोस्टिंग में बदलाव की चर्चा काफी दिनों से चल रही है। अब विधानसभा का मानसून सत्र समाप्त हो गया है। माना जा रहा है कि झंडावंदन के पहले प्रशासनिक फेरबदल हो जाएगा।

(लेखक पत्रिका समवेत सृजन के प्रबंध संपादक और स्वतंत्र पत्रकार हैं।)